सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार
" जो दूसरों का हक और छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है...!! "
अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-103 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, रविवार 03 मई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए

दशहरा मैदान, शांति नगर में नशाखोरी रोकने सीआरपीएफ के 5 जवानों की होगी तैनाती

दुर्ग भिलाई पुलिस द्वारा "जन मित्र योजना" की बैठक में लिया गया निर्णय, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं हम आपके दोस्त हैं : सुखनंदन राठौर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शांति नगर, वार्ड 14 के पार्षद अभिषेक मिश्रा की पहल पर दुर्ग भिलाई पुलिस द्वारा 1 मई को दशहरा मैदान में "जन मित्र योजना" की बैठक की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य था वार्ड के लोगों के नजदीक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनना और उनका निराकरण करना। वार्ड के लोगों की सर्वाधिक परेशानी दशहरा मैदान में शाम होते ही नशाखोरी को लेकर थी। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इस समस्या का तत्काल हल निकाला और अपने मातहत अधिकारियों को दशहरा मैदान की रूटीन चेकिंग का आदेश दिया।

बैठक में ही सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने सीआरपीएफ के पांच जवानों की ड्यूटी दशहरा मैदान में लगाने की बात कही जो शाम होते ही दशहरा मैदान की रूटीन चेकिंग करेंगे। वाडवासियों ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया।

बैठक में वार्ड के लोगों ने एक-एक कर अपनी समस्याएं बताई। जिसमें सर्वाधिक परेशानी दशहरा मैदान में हो रही नशाखोरी को लेकर ही थी। लोगों का कहना था कि शाम होते ही अनजान युवक इस मैदान में पहुंच जाते हैं और खुलेआम शराब का सेवन करते हैं। यह युवक इस वार्ड के न होकर दूर दराज जगहों से आते हैं। खासकर हॉस्टल में रहने वाले युवक ही ज्यादा होते हैं किसी ने इन्हें रोकने रोकने की कोशिश की तो वह लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। दशहरा मैदान में हो रही शराब खोरी के चलते वार्ड के लोगों का शाम को दशहरा मैदान में जाना लगभग बंद हो गया है। सड़क से गुजरने वालों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।

जन मित्र योजना की बैठक में उपस्थित वैशाली नगर थाना प्रभारी प्रभात मिश्रा का कहना था कि उन्हें लगातार यह शिकायत मिल रही है। जब हम युवकों को पकड़ने जाते हैं तो उनका कहना रहता है कि हम यहीं आसपास रहते हैं और यूं ही टहलने निकले हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कार्रवाई करने में काफी दिक्कत आती है। उन्होंने बैठक में उपस्थित पैरेंट्स से अनुरोध किया कि वह जागरूक हों और अपने बच्चों को दशहरा मैदान में जाने से रोके।

बैठक में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने वतर्मान में हो रहे साइबर ठगी को काफी विस्तृत रूप से बताया तथा बुजुर्गों और महिलाओं को इनसे सावधान रहने के उपाय बताएं। साइबर क्राइम, यातायात से संबंधित परेशानी होने पर उन्होंने इसके लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी तथा कहा कि पुलिस से बिल्कुल ना डरे। कोई भी समस्या हो तत्काल पुलिस से संपर्क करें, उनकी समस्या का हल निकलेगा।

बैठक के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने कहा कि हम आज यहां आप सभी लोगों को अपना दोस्त बनाने आए हैं। आप लोगों को पुलिस से डरने की बिलकुल जरुरत नहीं है हम भी आप लोगों की तरह ही है। पुलिस से बिल्कुल ना डरे और अपनी समस्या बेझिझक होकर बताएं। हेल्पलाइनो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन नंबरों को सेव करके रख लें और कभी भी किसी मुश्किल में पड़े तत्काल हमें याद करें, हम आपकी मदद के लिए ही हैं।

पार्षद अभिषेक मिश्रा का कहना था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच जो दूरी है उसे कम करना था। अक्सर देखा जाता है कि लोग पुलिस थाना जाने से हिचकते हैं कि वहां कोई सुनवाई नहीं होगी तथा उनसे कई सवाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस से किसी प्रकार भी डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस हमारी मदद के लिए ही है। बैठक में सैकड़ों की संख्या में वाडर्वासी उपस्थित हुए।

रायपुर पुलिस एक्शन : दिल्ली में नाइजीरियन ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में दबिश देकर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक तोचकू अफामे उर्फ प्रिंस चार्ल्स और उसके भारतीय साथी सन्नी शर्मा को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह नाइजीरिया से संचालित होकर रोजाना 10 से 50 लाख रुपये की ड्रग्स पूरे देश में सप्लाई कर रहा था। 6 महीने में 2 करोड़ के मनी ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है।

कुछ दिन पहले रायपुर पुलिस ने कोरियर से आई बीपी मशीन में छिपाकर भेजी गई ड्रग्स के साथ कृष्ण गोपाल अग्रवाल को पकड़ा था। उसी से पूछताछ में दिल्ली से चल रहे नाइजीरियन नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच आगे बढ़ी तो नाइजीरियन मास्टरमाइंड 'चिची' का नाम सामने आया जो नाइजीरिया से पूरा सिंडिकेट चला रहा है।

10 लाख रुपये कैश व 5 मोबाइल जब्त

छापे में पुलिस ने 10 लाख रुपये नगद और 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों से पूछताछ में 6 महीने में 2 करोड़ के ड्रग्स मनी ट्रांजेक्शन का पता चला है। गिरोह दिल्ली से पूरे देश में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था।

नाइजीरिया तक फैले तार

पुलिस जांच में सामने आया कि इस रैकेट का मुख्य सरगना 'चिची' नाइजीरिया में बैठकर सिंडिकेट चला रहा है। रायपुर पुलिस ने नाइजीरियन एंबेसी को पत्र लिखा है। साथ ही मास्टरमाइंड चिची के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए कोर्ट में आवेदन किया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। क्राइम ब्रांच नेटवर्क की बाकी कड़ियां खंगाल रही है। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई से अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट को बड़ा झटका लगा है।

पहली बार पकड़ा गया नाइजीरियन सरगना

रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंची और तोचकू अफामे को दबोच लिया। इसे ड्रग्स मामले में पहली बार गिरफ्तार किया गया है। पता चला कि यह 2024-25 में वीजा उल्लंघन के केस में दिल्ली की जेल भी जा चुका है। दूसरा आरोपी सन्नी शर्मा कमीशन पर नाइजीरियन गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इन्हीं खातों से ड्रग्स का पैसा इधर-उधर किया जाता था।

कांकेर में आईईडी ब्लास्ट ; डीआरजी के चार जवान हुए शहीद, सर्च अभियान तेज

मुख्यमंत्री व गृहमंत्री सहित विभिन्न वर्गों ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / कांकेर

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। शनिवार को आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें डीआरजी के तीन जवान मौके पर ही बलिदान हो गये। वहीं एक जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर से लाया गया, जहां इलाज के दौरान वह भी बलिदान हो गये। इस प्रकार कुल चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गये।

डीआरजी टीम प्रदेश के कांकेर-नारायणपुर सीमा क्षेत्र में नक्सलियों के छिपाए गए डंप की तलाश में निकली थी। इस दौरान आईईडी को हटाने की कोशिश में अचानक

ब्लास्ट हो गया, जिससे चार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। बस्तर आईजी सुंदरराज पट्टिलिंगम ने घटना की पुष्टि की है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। पूरे इलाके को घेर लिया है ताकि अन्य संभावित को खोजकर निष्क्रिय

किया जा सके। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नक्सलियों की संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सतकर्ता बढ़ा दी गई है।

नक्सली बिछा रखे हैं बारूद

बता दें कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर के जंगलों में नक्सलियों ने पूर्व में बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, जो समय-समय पर हादसे का सबब बनती रहती है। वहीं वहां पर तैनात फोर्स और ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सुरक्षाबल के जवान क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कर इन बारूदी सुरंगों की तलाश कर उन्हें निष्क्रिय करने में लगे हुए हैं।

फिर बढ़ी फोर्स की चिंता

बड़ी बात ये है कि यह घटना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 31 मार्च को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को सशस्त्र नक्सलमुक्त घोषित किया था। इसके बाद नक्सल मामले से जुड़ा यह पहला विस्फोट है। इससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोर्स की फिर चिंता बढ़ा दी है। वहीं सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

कैसे हुआ हादसा

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में आत्मसमर्पित माओवादी कैडरों की ओर से दी गई जानकारी और अन्य इनपुट के आधार पर माओवादियों के पूर्व में छिपाकर रखे गए सैकड़ों आईईडी बस्तर रेंज में पुलिस एवं सुरक्षा बलों की तरफ से बरामद कर निष्क्रिय किए गए थे, लेकिन आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जब कांकेर जिला पुलिस दल आईईडी को निष्क्रिय कर रहा था, तभी वह आकस्मिक रूप से विस्फोट हो गया, जिसके कारण मौके पर ही तीन पुलिस बल के सदस्य वीरगति को प्राप्त हो गये। वहीं एक जवान का रायपुर में इलाज के दौरान बलिदान हो गये।

पीएसयू कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की मांग, बीएकेएस ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-नईदिल्ली

भारत एलॉय कमर्चारी संघ (बीएकेएस) के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर देश की 291 पीएसयू में कार्यरत करीब 8 लाख गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए 2027 के वेतन समझौते हेतु वेज रिवीजन कमेटी गठित करने की मांग की है। यूनियन ने अधिकारियों की तर्ज पर कमर्चारियों के लिए भी एक समान पे रिवीजन कमेटी बनाने या चौथे पीआरसी की सिफारिशें लागू करने की मांग रखी है।

रणधीर कुमार ने पत्र में बताया कि देश में 291 पीएसयू प्रचालनरत हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में इनका कुल टर्नओवर 37.01 लाख करोड़ रुपये और कुल लाभ 3.09 लाख करोड़ रुपये रहा। सभी पीएसयू ने सरकार और शेयरधारकों को 1.39 लाख करोड़ रुपये का लाभांश भी दिया। पीएसयू में मैनपावर की स्थिति : अधिकारीः 2,32,088, नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरः 70,935, यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरः 25,481, कामगारः 7,83,728 हैं।

2027 से अधिकतर पीएसयू में गैर-कायर्पालक कमर्चारियों और अधिकारियों का वेतन समझौता/पे रिवीजन लंबित हो जाएगा। अभी DPE अधिकारियों के लिए पे रिवीजन कमेटी बनाती है, जिसमें एमजीबी, पर्क्स, पीआरपी का स्पष्ट जिक्र होता है। लेकिन कमर्चारियों के लिए सिर्फ गाइडलाइन जारी होती है, जिसमें मिनिमम गारंटी बेनिफिट और पर्क्स प्रतिशत साफ नहीं होता।

रणधीर ने सेल का उदाहरण देते हुए बताया कि 2017 के वेज रिवीजन में अधिकारियों को 15% एमजीबी, 35% पर्क्स और एरियर मिला, जबकि कर्मचारियों को सिर्फ 13% एमजीबी और 26.5% पर्क्स दिया गया।

अधिकारियों के पर्क्स अप्रैल 2020 से लागू हुए, लेकिन कर्मचारियों के नवंबर 2021 से। इससे कर्मचारियों का एरियर शून्य हो गया। अधिकारियों को कुल PBT का 5% पीआरपी मिलता है, जबकि कर्मचारियों को जटिल फॉर्मूले से मामूली बोनस दिया जाता है। यूनियन ने कहा कि अनुच्छेद 39(d), 14 और 16 के तहत 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत है। सेल में अधिकारी और कर्मचारी एक ही संगठन के हिस्से हैं, फिर वेतन संशोधन के मापदंड अलग क्यों?

पत्र में कहा गया कि सेल में NJCS कमेटी के 25 में से 20 यूनियन नेता गैर-निर्वाचित हैं और सालों से बिना श्रम कानून के मेंबर बने हैं। NJCS संविधान में Consensus की जगह Majority से फैसले लिए गए।

वेज रिवीजन कमेटी से होंगे ये फायदेः बेहतर प्रबंधनः हड़ताल, प्रदर्शन, टूल डाउन में कमी आएगी। औद्योगिक शांतिः पिछले दशकों में PSU में हड़ताल की मुख्य वजह वेतन और बोनस रही है। सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगाः सरकार और प्रबंधन के प्रति कर्मचारियों का विश्वास मजबूत होगा। समय-धन की बचतः अलग-अलग PSU में बैठकों पर होने वाले करोड़ों के खर्च और समय की बचत होगी। बीएकेएस ने मांग की है कि केंद्र सरकार सभी PSU के साढ़े सात लाख से अधिक यूनियनाइज्ड वकर्मैन के लिए वेज रिवीजन 2027 हेतु स्पष्ट एमजीबी, पर्क्स, पीआरपी वाली पे रिवीजन कमेटी गठित करे।

उधारी बनी हत्या की वजह : अंधे कत्ल का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

ग्राम कुम्हीचुआ, थाना कापू में 27 अप्रैल को मिले युवक के शव के मामले में रायगढ़ पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उधारी के 5 हजार रुपये को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने गला और मुंह दबाकर युवक की हत्या कर दी, फिर शव को घर के पीछे बाड़ी में फेंककर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की। कापू पुलिस ने आरोपी करमसाय नगेसिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

27 अप्रैल को देवव्रत तुरी, 30 वर्ष, का शव उसके निर्माणाधीन मकान के पीछे बाड़ी में संदिग्ध हालत में मिला था। मृतक के गले, कलाई और पीठ पर संघर्ष के निशान थे। नाक से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने और गले की हड्डी टूटने से मौत की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने इसे होमीसाइडल डेथ बताया। इसके बाद थाना कापू में अज्ञात के खिलाफ धारा 103(1) BNS के तहत हत्या का केस दर्ज हुआ।

जांच में सामने आया कि देवव्रत की पत्नी 2 साल से तीन बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। देवव्रत का माता-पिता और बहन से भी अक्सर विवाद होता

था। 26 अप्रैल की रात खाना खाकर सभी सो गए। सुबह बेटा रणबीर ने पिता को कमरे में न पाकर तलाश की तो शव बाड़ी में मिला।। पुलिस की तीन दिन की पूछताछ में अहम सुराग मिला। पता चला कि गांव के करमसाय नगेसिया और देवव्रत के बीच पैसों का पुराना विवाद था। मार्च में करमसाय का परिवार देवव्रत के घर झगड़ा करने भी आया था।

शादी से लौटते वक्त किया कत्ल

संदेह पर करमसाय नगेसिया, 42 वर्ष, को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि 6 साल पहले देवव्रत ने उससे 5 हजार रुपये उधार लिए थे। ब्याज समेत रकम बढ़ गई, पर देवव्रत टालमटोल करता रहा। 11 मार्च को पैसा मांगने पर दोनों परिवारों में गाली-गलौच हुई। गांव में पंचायत भी बैठी, पर पैसा नहीं मिला।

26 अप्रैल की रात करीब 11 बजे शादी से लौटते वक्त करमसाय ने देवव्रत को घर के पास देखा। पुरानी रंजिश में उसने देवव्रत को दरवाजे पर पकड़ा। मुंह और गला दोनों हाथों से दबाकर जमीन पर पटक दिया। मौत होने तक दबाए रखा। फिर शव उठाकर घर के पीछे बाड़ी में फेंक दिया ताकि मामला छिप जाए।

एसएसपी का सख्त संदेश

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा, उधारी विवाद में हत्या कर साक्ष्य छुपाने जैसा जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आमजन किसी भी विवाद का समाधान कानून और संवाद से करें।

पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका

एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन, एडिशनल एसपी अनिल सोनी और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी, आरक्षक विभूति सिंह, संजीव पटेल, दिनेश गोंड, महिला आरक्षक संगीता लकड़ा और साइबर सेल टीम ने प्रोफेशनल तरीके से केस सुलझाया।

सुशासन तिहार के मौके पर प्रदेशव्यापी दौरे में निकले मुख्यमंत्री साय

रायपुर। राज्य शासन के महत्वपूर्ण अभियान सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस लाइन हेलीपेड रायपुर से रवाना हुए। इस अभियान में मुख्यमंत्री श्री साय आम नागरिकों से रूबरू होकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का फीडबैक लिया। उल्लेखनीय है कि 1 मई से प्रारम्भ सुशासन तिहार 10 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल भी हुए रवाना

प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने ली सुशासन तिहार की तैयारियों की समीक्षा बैठक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े दुर्ग, बालोद, बस्तर एवं मोहला-मानपुर जिलों के प्रशासनिक अधिकारी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुशासन तिहार के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बालोद, बस्तर एवं मोहला-मानपुर जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए।

समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मनरेगा भुगतान, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड वितरण, राजस्व प्रकरण, शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेयजल व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि शिविरों में पुलिस विभाग द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा, जहां नशा मुक्ति, यातायात नियम, साइबर फ्रॉड (टोल फ्री नंबर 1092) सहित अन्य जागरूकता संबंधी जानकारी दी जाएगी।

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सुशासन तिहार में विशेष रूप से राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए और कोई भी मामला समय-सीमा से बाहर न रहे। उन्होंने नक्शा-खसरा निःशुल्क उपलब्ध कराने, बंटवारा, सीमांकन और नामांतरण जैसे मामलों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिविरों की जानकारी जनप्रतिनिधियों, पंचायत एवं समाज प्रमुखों तक समय पर पहुंचाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में ह्वसेवा सेतुह्व पोर्टल के प्रचार-प्रसार के लिए शिविरों में स्टॉल लगाने और डेमो देने की व्यवस्था करने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार का लेन-देन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। इसके अलावा खाद वितरण, विद्युत आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने, खराब बोर सुधारने, पाइपलाइन बिछाने और जरूरत पड़ने पर पानी टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिविर स्थलों पर पेयजल, कूलर और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। उन्होंने पुलिस विभाग को स्कूल-कॉलेजों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा साइबर अपराध, नशा और यातायात नियमों पर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने और ग्राम पंचायतों में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन का लाभ उठा सकें। प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर सुशासन तिहार को सफल बनाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। एनआईसी दुर्ग के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी, एसडीएम उत्तम ध्रुव, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई-चरोदा आयुक्त दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

खास खबर

दुर्ग में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने की कारवाई तेज

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग मिनी माता चौक पुलगांव से जेल तिराहा चौक तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। साथ ही पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य को भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती और लगातार निरीक्षण का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। पोटिया चौक सहित कई स्थानों पर अतिक्रमणकर्ताओं ने कारवाई से पहले ही स्वयं अपने कब्जे हटाने शुरू कर दिए हैं, जिससे सड़क चौड़ीकरण का कार्य आसान हो गया है।

जानकारी के अनुसार करीब 120 से अधिक लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण किए गए थे। इनमें दुकानें, बाउंड्रीवाल, शेड और अन्य निर्माण शामिल हैं, जो प्रस्तावित कार्य में बाधा बन रहे थे। निगम और PWD की संयुक्त टीम इन अवरोधों को हटाने में लगातार जुटी हुई है। अतिक्रमण दल के प्रभारी सहायक अभियंता गिरीश दीवान ने बताया कि 30 अप्रैल से लगातार निरीक्षण कर कारवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि संबंधित लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा निगम द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में होने वाले नुकसान के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इस अभियान में उप अभियंता सिद्धार्थ साहू, विनोद मांझी, अतिक्रमण प्रभारी ईश्वर वर्मा और परमेश्वर सहित टीम के अन्य सदस्य शामिल हैं, जो नियमित मॉनिटरिंग कर कार्रवाई को प्रभावी बना रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इस कारवाई से सड़क निर्माण कार्य में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर, सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर विकास कार्यों में सहयोग करें।

आयुक्त सुमित अग्रवाल के साथ कर्मचारी संघ की बैठक : विभिन्न मांगों पर हुई विस्तार से चर्चा

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग में आयुक्त सुमित अग्रवाल के साथ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ की परामशर्दात्री समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा, महामंत्री अनिल सिंह सहित पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में पूर्व में लिए गए निणर्यों के क्रियान्वयन पर जोर देते हुए चतुर्थ श्रेणी कमर्चारियों को वर्दी शीघ्र प्रदान करने की मांग रखी गई।

साथ ही सभी कमर्चारियों को प्रतिमाह वेतन भुगतान के पश्चात वेतन पत्रक उपलब्ध कराने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संघ द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नई भर्ती पर रोक लगाने तथा रिटायर्ड कर्मचारियों की प्लेसमेंट भर्ती पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इसके अलावा कमर्चारियों के वेतन में कटौती या वेतन रोकने जैसी कारवाई को अनुचित बताते हुए इस पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। बैठक में यह भी मांग रखी गई कि भविष्य निधि एवं एन.पी.एस. की राशि प्रतिमाह वेतन के साथ ही नियमित रूप से जमा कराई जाए तथा रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

जलघर विभाग में कार्यरत कमर्चारियों की कार्य परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया गया कि कई स्थानों पर कर्मचारियों से लगातार 24 से 48 घंटे तक कार्य लिया जा रहा है, जबकि भोजन एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस पर रोक लगाने एवं कर्मचारियों के हितों का विशेष ध्यान रखने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया गया कि ड्यूटी आदेश व्हाट्सऐप के माध्यम से अनियमित समय पर जारी करने के बजाय कार्यालयीन समय में जारी किए जाएं तथा विशेष परिस्थितियों में संबंधित कर्मचारियों को फोन के माध्यम से सूचित किया जाए। बैठक में संघ के पदाधिकारी दुर्गेश गुप्ता, शशिकांत यादव, ईश्वर वर्मा, हेमलता वर्मा, योगेंद्र वर्मा, राजू बक्शी, गंगाधर ठाकरे, उमेश यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने ली नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के सख्त पालन के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के तहत अब कचरे को केवल गीला और सूखा नहीं, बल्कि चार श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा- गीला कचरा (रसोई और बगीचे का अपशिष्ट) सूखा कचरा (प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु) सेनेटरी वेस्ट (डायपर, सेनेटरी नैपकिन) आदि जिन्हें अलग से लपेट कर देना होगा। स्पेशल केयर वेस्ट (दवाइयां, पेंट के डिब्बे, बल्ब, बैटरी)।

कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में इन चारों श्रेणियों के लिए पृथक बॉक्स सुनिश्चित करें। नए नियमों के अनुसार कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया (संग्रहण से लेकर निपटान तक) को एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

होटल, मैरिज गार्डन, बड़ी आवासीय सोसायटियों, अपार्टमेंट, कॉलेज छात्रावास परिसर, सामुदायिक भवन आदि जो प्रति दिवस 100 किलोग्राम या उससे अधिक गीला कचरा उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने गीले कचरे का निपटान स्वयं के परिसर के भीतर ही बायो डाइजेस्टर मशीन अथवा पिट कम्पोस्टिंग के माध्यम से करना होगा। साथ ही समस्त बल्क वेस्ट जेनरेटरों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करना भी अनिवार्य होगा। बल्क वेस्ट जेनरेटरों को निकाय से विस्तारित बल्क वेस्ट जेनरेटर जिम्मेदारी प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को नियमानुसार जुर्माना देना होगा।

इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया की समस्त आवासीय सोसायटी एवं बड़े परिसरों जो बलक वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आएंगे उनको गीले कचरे के कंपोस्टिंग के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहायता भी प्रदान की जाए ताकि वह निर्धारित समय सीमा में अपने परिसर के अंदर ही कंपोस्टिंग हेतु मशीन अथवा पीट की स्थापना कर सकें। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा के सिद्धांत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कलेक्टर ने पुराने डंपिंग साइट्स पोटियाकला तथा जामुल के बायो-माइनिंग और बायो-रेमेडिएशन के कार्य को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट के निष्पादन हेतु निकायों के समीपस्थ केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुमोदित रिसाइकलरों से संपर्क कर अनुबंध स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता को नए नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जाएं। वार्ड पार्षदों और स्वच्छता दीदियों के माध्यम से नागरिकों को 4-स्ट्रीम पृथक्कीकरण के लाभ समझाए जाएं।

बैठक में नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा आयुक्त दशरथ राजपूत, नगर निगम भिलाई स्वच्छता प्रभारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सीएमओ, स्वच्छता निरीक्षक, पर्यावरण मंडल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के एमडी ठाकुर ही होंगे अध्यक्ष

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष के विवाद पर अब विराम लग गया है। महासभा के एमडी ठाकुर ही अध्यक्ष होंगे। 17 फरवरी 2026 के उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले कमलेश ध्रुव की याचिका को उपसचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है, साथ ही न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2025 के चुनाव को निरस्त करने एवं नया चुनाव करने संबंधी पंजीयन फॉर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा 8 जनवरी 2026 को दिए आदेश को यथावत रखा है। उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने 17 अप्रैल 2026 को जारी किए अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि पंजीयन फॉर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ के पारित आदेश 8 जनवरी 2026 के पालन में महासभा द्वारा पुनः 17 फरवरी 2026 को मतदान प्रणाली से चुनाव संपन्न करा कर धारा 27 के तहत फॉर्म्स एवं संस्थाएं में जानकारियां ऑनलाइन जमा की गई है। वैध सदस्यों के बीच महासभा का विधिवत रूप से चुनाव संपन्न होने के कारण कमलेश ध्रुव की अपील याचिका खारिज कर फॉर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा 8 जनवरी 2026 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। इस आदेश से कमलेश ध्रुव के अध्यक्ष होने का दावा भी खत्म हो गया है। जिससे केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष एमडी ठाकुर के समथर्कों और समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है। मीडिया से चर्चा में महासभा के अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने बताया कि पूर्व में केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ का 10 सितम्बर 2025 में चुनाव हुआ था। चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की लापरवाही की वजह से बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी व अन्य जिलों से फर्जी मतदान की शिकायतें सामने आई थी। जो लोग समाज के सदस्य नहीं थे, उन लोगों ने भी मतदान कर दिया था। बेमेतरा में दो-दो जिला अध्यक्षों द्वारा फर्जी मतदान कराया गया। जिस पर चुनाव के दौरान आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मतदान उपरांत कमलेश ध्रुव द्वारा अपने आप को अध्यक्ष प्रचारित करते हुए शपथ भी ग्रहण कर लिया गया था। केंद्रीय अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने बताया कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया की 28 अक्टूबर 2025 को पंजीयन फॉर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ में पूरे दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई थी। शिकायत पर जांच उपरांत फॉर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा 8 जनवरी 2026 को आदेश आया। जिसमें चुनाव को निरस्त कर वैध सदस्यों के बीच नया चुनाव करने के आदेश दिए गए। इसके उपरांत महासभा द्वारा वैध मतदाताओं की सूची का फॉर्म्स एवं संस्थाएं से अनुमोदन कराया गया और 17 फरवरी 2026 को नया चुनाव कराया गया।

शिक्षा मंत्री यादव की पहल, दुर्ग के 11 स्कूल बन रहे स्मार्ट, अगले सत्र से बच्चे पढ़ेंगे स्मार्ट क्लास में

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्षेत्र के कुल 21 शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 11 विद्यालयों को पूर्णतः स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे अब स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं डिजिटल कंटेंट के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के उरला, तितुरडीह एवं शक्तिनगर स्थित शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं स्मार्ट स्कूल तैयार हो रहे है। शिक्षा

विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों में डिजिटल तकनीक आधारित आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लास की पहल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं भविष्य उन्मुख शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हो रही है।

प्रदेश सरकार स्पष्ट संकल्प है कि शासकीय विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण, संसाधन एवं अधोसंरचना निजी शिक्षण संस्थानों के समकक्ष विकसित हों, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान अवसर और उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध हो सके।

दुर्ग में विकसित किए जा रहे स्मार्ट स्कूलों में बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं एवं परिसर की दीवारों पर आकर्षक और ज्ञानवर्धक प्रिंट रिच वातावरण तैयार किया जा रहा है। इन दीवारों पर विषयवार महत्वपूर्ण जानकारी, चित्र, चार्ट, सूत्र, मानचित्र, भाषा विकास सामग्री और प्रेरणादायक संदेशों को सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े और वे सहज रूप से सीख सकें। प्रिंट रिच वातावरण के माध्यम से विद्यार्थी हर समय अपने आसपास उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से जुड़कर निरंतर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहेंगे, जिससे वे समझ और रचनात्मकता की ओर ध्यान आकर्षित होगा। स्मार्ट स्कूलो में तैयार किये जा प्रिंट रिच वातावरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों के हिसाब से चित्र बनाये गये है हाई स्कूल में प्रैक्टिकल वर्क के अनुरूप चित्र बनाये गये है।

कलेक्टर ने जनगणना प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले में भी दो चरणों में जनगणना होगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ) कार्य 01 मई से 30 मई 2026 तक किया जायेगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शुक्रवार 1 मई को कलेक्टोरेट परिसर से जनगणना प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ जिले के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा।

इस अवसर पर एडीएम वीरेन्द्र सिंह, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव, तहसीलदार एवं जार्ज अधिकारी दुर्ग ग्रामीण प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, जनगणना सुपरवाईजर एवं प्रगणक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सिंह ने जनगणना प्रचार रथ रवानगी के पश्चात

तहसील दुर्ग ग्रामीण चार्ज अंतर्गत आने वाले ग्राम डूमरडीह जहां सीआईएसएफ आरटीसी कैम्प है, में भ्रमण कर जनगणना कार्य का अवलोकन किया। साथ ही सुपरवाईजर और प्रगणकों से कार्य प्रगति की जानकारी ली।

उल्लेखनीय है कि जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रगणकों द्वारा जनगणना संबंधित आवश्यक जानकारी ली जाएगी। इस दौरान मकान सूचीकरण के दौरान भवन संख्या, मकान के फर्श, दीवारों और छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री के साथ-साथ मकान के उपयोग और उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण दर्ज किया जाएगा। परिवार संबंधी जानकारी के अंतर्गत परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, मुखिया का नाम व लिंग, मुखिया की जाति श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य), मकान के स्वामित्व की स्थिति, उपलब्ध कमरों की संख्या और परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या की जानकारी ली जाएगी। इसी प्रकार मूलभूत सुविधाओं के तहत पेयजल का मुख्य स्रोत व उसकी उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता व प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नानघर की सुविधा, रसोईघर की स्थिति, एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता और खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे।

परिसंपत्तियों के विवरण में रेडियो/ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप/कंप्यूटर, टेलीफोन/मोबाइल/स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड और कार/जीप/वैन की उपलब्धता की जानकारी संकलित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियों में परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज और जनगणना संबंधी संचार के लिए मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। ज्ञात हो कि यह चरण जनसंख्या गणना का आधार तैयार करता है, जिसमें नागरिकों की सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी।

मुस्लिम समुदाय ने किया हज यात्रियों का सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की ओर से इस साल हज के मुबारक सफर पर जा रहे जायरीनों का इस्तकबाल किया गया। जामा मस्जिद सेक्टर-6 के कम्युनिटी हॉल में हुए इस आयोजन में दुर्ग-भिलाई के 60 से ज्यादा जायरीन शामिल हुए। सभी का गुलपोशी और तोहफे के साथ इस्तकबाल किया गया। इस दौरान जामा मस्जिद सेक्टर-6 के इमाम हाफिज इकबाल अंजुम हैदर, हाफिज असगर अली और हाफिज कारी शहादत हुसैन ने आजमीने हज को मुबारकबाद दी और हज की अहमियत बयान की। निजामत मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन ने की।

आयोजन में इस साल हज पर जाने वाले खुशकिस्मतों में इफ्तेखार खान, मुस्तफा अली,

मोहम्मद सलीम, हामिद खान, शफी मास्टर, मोहम्मद मोहसिन, रफी उल हक, मंजूर आलम, इस्माइल गौरी, सय्यद यूनुस अली, रिजवान, नसीरुद्दीन, मोहम्मद फहीम, मिर्जा इरफान बेग, फिरोज हुसैन, अब्दुल रशीद, अफजल अनीस, अब्दुल हक, शेख सखावत, डॉ.शेख आदिल, हाजी गुलाम रसूल, मंजर आलम, गुलाम हसीब अंसारी, जाकिर अहमद काजी, अब्दुल मजीद, हामिद उल्ला खान, हमीद उद्दीन सिद्दीकी, अब्दुल वहीद, हसन कोया, इसराइल सिद्दीकी, इश्तियाक अहमद, अजमल, जी एम अंसारी, एम आई खान के साथ 37 महिला जायरीनों ने शिरकत की। सभी का इस्तकबाल इंतेजामिया कमेटी ने किया। आखिर में सलाम पढ़ा गया और दुआए खैर की गई।

गांव-गांव पहुंच रहा सुशासन, जनसमस्या निवारण शिविरों की हुई शानदार शुरुआत

नवागढ़ के ग्राम सरखों में लगा पहला शिविर, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में 1 मई से 10 जून तक जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

इसी क्रम में जांजगीर चांपा के जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम सरखों में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास की विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर का निरीक्षण जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली गई।

शिविर में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों एवं मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबियां भी सौंपी गईं। शिविर में कुल 1334 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1265 मांग एवं 69 शिकायतें शामिल हैं। कार्यक्रम में विधायक जांजगीर-चांपा ब्यास कश्यप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व संसदीय सचिव अंबेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए और सभी आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में निराकरण किया जाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य प्रशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

पूर्व संसदीय सचिव अंबेश जांगड़े एवं जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी ने भी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि जिले में शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है और प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। उन्होंने

राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु कैम्प कोर्ट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा सभी आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग पर बल दिया। शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, श्रम, वन, जल संसाधन, विद्युत सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

खास खबर

स्कूटी पर निकले अरुण साव, नगर भ्रमण कर विकास कार्यों का लिया जायजा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक अरुण साव ने लोरमी नगर में स्कूटी से भ्रमण कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रानीगांव में गार्डन, तालाब और मुक्तिधाम निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री साव ने प्रवेश द्वार, नाली निर्माण और मनियारी नदी पर बन रहे पुल की प्रगति की जानकारी लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बस स्टैंड जिम में युवाओं से संवाद किया और स्लम स्वास्थ्य योजना के मेडिकल यूनिट का अवलोकन कर स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा। साथ ही नालंदा परिसर (आधुनिक लाइब्रेरी) के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भ्रमण के दौरान बच्चों और महिलाओं से आत्मीय मुलाकात कर उनका सुख-दुख जाना। उन्होंने ब्राह्मण पारा में जादूगर द्वारा दिखाए जा रहे जादू का आनंद भी लिया। श्री साव ने लोरमी में अपने विधायक कार्यालय में स्थानीय नागरिकों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की और जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने राम्हेपुर स्थित शिव मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास से ही जनता का भरोसा मजबूत होता है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने माँ बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अचर्ना की

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने डोंगरगढ़ में माँ बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अचर्ना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान सांसद संतोष पाण्डेय, महापौर मधुसूदन यादव, समाज सेवी कोमल सिंह राजपूत, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्रीमती पूर्णिमा साहू, पूर्व विधायक विनोद खांडेकर, माँ बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष अनिल गट्टानी सहित ट्रस्ट समिति के अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

आम जनता की सुविधाओं पर फोकस ; बिजली, पानी और आवास को प्राथमिकता

मंत्री गजेन्द्र यादव ने सुशासन तिहार की तैयारियों की विभागवार ली समीक्षा बैठक

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, खाद-बीज भंडारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत एवं पेयजल जैसी जनजीवन से जुड़ी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के मिल सके।

मंत्री श्री यादव ने दुर्ग जिले के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सर्किट हाउस के सभाकक्ष में सुशासन तिहार की तैयारियों एवं विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूर्ण जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री यादव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि समय-समय पर शिविरों का औचक निरीक्षण कर जनता से सीधे फीडबैक लेंगे।

राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरणरू लंबित राजस्व प्रकरणों, विशेषकर समय-सीमा पार कर चुके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

शिक्षा एवं मॉडल स्कूल दुर्ग जिले में एक स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही, आदर्श कन्या विद्यालय में छात्राओं को और जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाए। छात्रावासों का सुधार- जिले के 34 छात्रावासों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने आदिवासी विकास आयुक्त को व्यापक निरीक्षण के निर्देश दिए। भोजन, स्वच्छता और सुरक्षा में कोई कमी पाए जाने पर तत्काल सुधार करने को कहा।

खाद्य एवं राशन वितरण- लंबे समय से एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों की समीक्षा कर नए पात्र लोगों को अवसर दिया जाए। दुकानों में आगामी 3 महीने का राशन स्टॉक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। स्वास्थ्य सेवाएँ- प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य हो। गाँवों में बीपी और शुगर की जाँच हेतु विशेष अभियान चलाया जाए।

मनरेगा एवं पौधारोपण- जून माह से पूर्व व्यापक पौधारोपण हेतु वनमण्डाधिकारी को भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए।

कृषि एवं सिंचाई- सोसायटियों में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। किसानों को कम पानी वाली फसलों (सोयाबीन, अरहर, चना) के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिले की 19 नई सोसायटियों में बीज की कमी न होने पाए।

विद्युत व्यवस्था- मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत सर्वे कर आवश्यक बिजली पोल और अधोसंरचना का विस्तार किया जाए ताकि निर्बाध आपूर्ति बनी रहे। मंत्री श्री यादव ने अंत में सख्त लहजे में कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों या आँकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, दुर्ग जनपद अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वरी देवांगन, कलेक्टर अभिजीत सिंह, वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, अपर कलेक्टर विरेन्द्र सिंह, विभिन्न नगर निगमों के आयुक्त (भिलाई, दुर्ग, चरोदा, रिसाली) एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अबूझमाड़ की मेधा ने गढ़ दिया 'नारायणपुर' में शिक्षा के शिखर पर वनांचल की गौरवगाथा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर जिसे कभी दुर्गम और 'अबूझ' माना जाता था, आज उसी नारायणपुर ने अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा पूरे प्रदेश में मनवा लिया है। साल 2026 की बोर्ड परीक्षा के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बस्तर के घने जंगलों और अबूझमाड़ की वादियों में अब केवल संघर्ष की गूँज नहीं, बल्कि सफलता का शंखनाद सुनाई दे रहा है। कक्षा 10वीं में समूचे छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त करना नारायणपुर के लिए महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक शैक्षणिक क्रांति है।

जिले की इस अभूतपूर्व सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों और जिला प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि नारायणपुर के बच्चों ने आज जो कर दिखाया है, वह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। अबूझमाड़ की माटी से निकलकर प्रदेश की मेरिट सूची में जगह बनाना यह साबित करता है कि हमारी सरकार की 'शिक्षा-पहुँच' नीति सफल हो रही है। नारायणपुर अब केवल अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेधा के

लिए भी जाना जाएगा। इन नौनिहालों ने नक्सलवाद और पिछड़ेपन के अंधेरे को शिक्षा की रोशनी से परास्त कर दिया है।

इतिहास गवाह है कि विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। पिछले एक साल में नारायणपुर ने जो परिवर्तन देखा है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्ष 2025 में 84.96% के साथ 10वें स्थान पर रहने वाला यह जिला, महज एक साल में 94.80% की सफलता दर के साथ सीधे प्रदेश में दूसरे स्थान पर जा पहुँचा। वहीं, 12वीं के परिणामों में भी जिले ने अपनी रैंकिंग में 7 अंकों का शानदार सुधार करते हुए 12वां स्थान हासिल किया है।

इस सफलता की पटकथा उन सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में लिखी गई, जहाँ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने मिलकर 'मिशन मोड' में काम किया। कलेक्टर के मार्गदर्शन में बोर्ड परीक्षाथियों के लिए विशेष कायर्योजना तैयार की गई। मॉडल टेस्ट, प्री-बोर्ड परीक्षाओं और 'रिमेडियल कक्षाओं' के जरिए कमजोर विद्याथियों को मुख्यधारा में लाया गया। शिक्षकों के समर्पण और प्रशासन की सतत निगरानी ने वनांचल के बच्चों के भीतर 'परीक्षा के डर' को 'जीत के उत्साह' में बदल दिया।

जब हम आधारभूत संरचना की बात करते हैं, तो अक्सर सड़कों की गिनती होती है। परंतु नारायणपुर ने साबित किया है कि वास्तविक विकास 'मानव पूंजी' का विकास है। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में विशेष उपस्थिति अभियान चलाकर और समयबद्ध पाठ्यक्रम पूर्ण कर प्रशासन ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया, जहाँ शिक्षा एक उत्सव बन गई। अबूझमाड़ के बच्चे अब केवल वनों के संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने की दौड़ में प्रदेश के अन्य विकसित जिलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभिभावकों के साथ सतत संवाद और शिक्षकों का अटूट परिश्रम ही इस ऐतिहासिक सफलता का मूल मंत्र है। नारायणपुर की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश है—कि संसाधनों की कमी कभी प्रतिभा का मार्ग नहीं रोक सकती, बशर्ते संकल्प विष्णु देव साय के 'सुशासन' जैसा सुदृढ़ हो। आज 'अबूझ' अब 'बूझ' में बदल चुका है और शिक्षा की यह मशाल अब रुकने वाली नहीं है।

कृषि मंत्री ने राज्य के 3556 बीज उत्पादक किसानों को 8.2 करोड़ रूपए प्रोत्साहन राशि का किया अंतरण

बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है : कृषि मंत्री रामविचार नेताम

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 3556 बीज उत्पादक किसानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का 8 करोड़ 01 लाख 97 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में ऑनलाईन अंतरित किया। यह राशि मंडी निधि के तहत हितग्राहियों को प्रदाय किया गया। इस मौके पर प्रदेश के सैकड़ों किसान प्रक्रिया केंद्रों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। मंत्री श्री नेताम ने बीज उत्पादक किसानों से चर्चा कर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए उनका हौसला बढ़ाया साथ ही निगम के एक वर्ष के उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार विशेष रूप से उपस्थित थीं।

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों ने अथक मेहनत एवं परिश्रम से बीज उत्पादन किया है। उनके इस मेहनत का फल उन्हें मिले इस उद्देश्य से प्रोत्साहन की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित किया गया। उन्होंने किसानों को धान के अलावा दलहन-तिलहन एवं मिलेट्स और सब्जी-भाजी व अन्य आय मूलक फसलें लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गरमी के दिनों में धान की खेती से बचना चाहिए। क्योंकि

इसमें पानी अधिक लगता है। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धान की जगह किसानों को दलहन-तिलहन की खेती करनी चाहिए। इससे मिट्टी की उवर्रा शक्ति बनी रहती है। वहीं पानी की खपत भी कम होती है।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि बीज की गुणवत्ता पर सरकार की साख जुड़ी होती है। उन्होंने बीज उत्पादक किसानों को ईमानदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन बीज उत्पादन करने की अपील की। उन्होंने किसानों से कहा कि प्रदेश किसानों के लगन और मेहनत से बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के लिए प्राथमिकता पर है। उन्होंने मिल-जुलकर छत्तीसगढ़ को कृषि उत्पादक राज्यों के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

बीज निगम के अध्यक्ष चन्द्रहास चंद्राकर ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और मंत्री श्री नेताम के मार्गदर्शन में निगम द्वारा समय पर बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। आगे भी प्रयास रहेगा कि समय पर किसानों के मेहनत का सम्मान हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की भाव से धान खरीद कर देश में किसानों का मान बढ़ाया है। उन्होंने इस मौके पर किसानों की ओर से कुछ मांगे भी रखी, जिसका मंत्री श्री नेताम ने गंभीरता के साथ विचार करने का आश्वासन दिया। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अजय अग्रवाल ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। मंत्री श्री नेताम ने इस अवसर पर कवर्धा, अंबिकापुर और रायपुर जिले के किसानों से चर्चा कर हालचाल जाना। किसानों ने वर्ष 2024-25 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मंत्री रामविचार नेताम और निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर के प्रति आभार व्यक्त किया।

संपादकीय

राहतकारी हो आईसीयू गहन चिकित्सा का देखभाल

इन दिशानिर्देशों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से स्थिर हो चुके या जिन मरीजों के अंगों को बाहरी सहायता अथवा शारीरिक निगरानी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। उन्हें अन्य सामान्य वार्डों में स्थानांतरित किया जा सकता है। निश्चित रूप से न्यायालय के ये निर्देश चिकित्सकीय और नैतिक दोनों ही हैं। जो बताते हैं कि जरूरी न होने के बावजूद मरीज को लंबे समय तक आईसीयू में रखना अनुचित है। यह एक हकीकत है कि मानकीकृत आईसीयू प्रोटोकॉल के अभाव में एक अस्पष्ट स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज से जुड़े निर्णय असमंजस का शिकार होकर रह जाते हैं। वास्तव में आईसीयू में भर्ती मरीजों के तिमारदारों को चिकित्सा प्रक्रिया की गहन जानकारी अक्सर नहीं होती है। वे केवल चिकित्सक के दिशा–निर्देशों पर ही निर्भर होकर रह जाते हैं। यही वजह है कि अस्पताल प्रबंधन के रहमो–करम पर मरीज को महंगे आईसीयू में लंबे समय तक भर्ती रहने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती रहने के बावजूद मरीज को उपचारीय लाभ नहीं मिल रहा होता है।

सही मायनों में सुप्रीम कोर्ट के ये दिशानिर्देश एक सरल व सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इस विसंगति को दूर करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी अस्पताल का आईसीयू मरीज की अनिश्चितकालीन देखभाल के लिए नहीं होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष अदालत ने समस्या के यथाशीघ्र समाधान की जरूरत पर बल दिया है। अदालत ने डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को संरक्षित करते हुए चिकित्सा संस्थानों व अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है।

इस दिशा में व्यवस्थागत मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिसमें नर्स व मरीज के अनुपात, विशेषज्ञ पयर्वेक्षण, मानक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कराना एक सराहनीय पहल कही जाएगी। निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में भारी असमानता है, ये न्यूनतम मानदंड अधिक न्यायसंगत देखभाल के लिए आधार बन सकते हैं। सही मायनों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही निर्देश नीति के क्रियान्वयन हेतु तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन विगत के अनुभव बताते हैं कि एक अच्छे इरादे वाली काययोजना तब अपने लक्ष्य पाने में विफल हो जाती हैं जब उसका क्रियान्वयन आधे–अधूरे ढंग से किया जाता रहा है।

निश्चित रूप से निगरानी ढांचे और समन्वित राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई पर अदालत की पहल सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी अनुपालन की सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्त पोषण और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करेगी। साथ ही दक्षता के अलावा, मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गहन चिकित्सा कक्ष में लंबे समय तक भर्ती रहना मरीजों और उनके परिवारों के लिए बेहद कष्टदायक होता है। स्थिर मरीजों को कम स्तर पर देखभाल की जरूरत वाले वार्डों में स्थानांतरित किए जाने से न केवल अनावश्यक चिकित्सा खर्च बचता है। बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण का भी परिचायक है। निश्चित रूप से आईसीयू के लिए एकसमान मानदंड लागू करने का प्रयास भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिर्ता लाने और तकर्संगत निर्णय लेने को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।

शांति स्थापना में मीडिया की आध्यात्मिक दृष्टि मददगार

नरेश कौशल

वर्तमान अशांत वैश्विक दौर में ब्रह्माकुमारी मिशन आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से शांति स्थापना के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इस मिशन के साथ–साथ मीडिया भी यदि शांति के लिए हो रहे प्रयासों में अपना भरसक योगदान करने लगे तो इस दिशा में विश्व जनमत और मजबूत हो सकता है।

ओम ? शांति। वैसे तो ओम रूपी इस अपार शांति सागर में मेरे विचार गागर में एक बूंद की माफिक होंगे। फिर भी वैश्विक शांति के लिए मीडिया की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर अपने अनुभव, अपने विचार और सुझाव रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिये, नीड ऑफ ग्लोबल पीस, रोल ऑफ मीडिया के विषय पर चर्चा की शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं :– कलम उठे तो अमन की कहानी लिखी जाये, हर एक खबर में इंसानियत दिखी जाये।

निस्संदेह, विश्व आज सर्वाधिक अशांत दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ भय और असुरक्षा का माहौल है। व्यक्ति, राष्ट्र से लेकर विश्व स्तर तक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना काल से लेकर, यूक्रेन युद्ध और आजकल अमेरिका–इस्राइल और ईरान द्वंद्व तक के संघर्ष ने दुनिया के अरबों लोगों के जीवन को अशांत बनाकर रख दिया है। हाल के दशकों में वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद दुनिया को एक वैश्विक गांव बनाने का जो सपना देखा गया था वह ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में नीड ऑफ ग्लोबल पीस एंड रोल ऑफ मीडिया विषय आज निश्चित रूप से समय की मांग है।

आज जहां संयुक्त परिवार बिखर कर एकल में सिमटने लगे हैं, दाम्पत्य जीवन में टूटन बढ़ रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी जी रही युवा पीढ़ी में सहनशीलता, धैर्य का क्षरण हो रहा है। परिवार से लेकर समाज तक और समाज से लेकर देश–विदेश तक मानव मनोविकारों का संत्रास हमारे भाईचारे को, विश्व बंधुत्व के हमारे सपनों को चकनाचूर कर रहा है। सोचा तो यह था कि तकनीकी उन्नति समाज को और देशों को जोड़ने का काम करेगी, लेकिन उलटे दुनिया संघर्षों में उलझी दिखायी पड़ रही है। पूरी दुनिया में युद्ध, मृत्यु, तबाही, विस्थापन और मानवीय विपदाओं का अंतहीन सिलसिला चल निकला है। निस्संदेह ब्रह्माकुमारी मिशन विपदाओं के इस सिलसिले को थामने में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से अथक प्रयास कर रहा है। इस मिशन के साथ–साथ मीडिया भी शांति के लिए हो रहे प्रयासों में अपना भरसक योगदान करने लगे, अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लग जाये तो इस दिशा में विश्व जनमत और मजबूत हो सकता है। पत्रकार युद्ध का सच बताने के साथ–साथ अगर बुद्ध के सच को भी उजागर करें तो यह समूची मानवता के लिये एक कल्याणकारी ऋषिकर्म होगा। संयोग से आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसके लिए आप सबको बधाई!

इस मंच से उल्लेख जरूरी है कि जिस नारी के महत्व, जिस नारी की शक्ति को आज विश्वभर में पहचान मिलने लगी है। जिस नारी का वंदन करते हुए हमारी देश–प्रदेश की सरकारें 33 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रयास और प्रचार कर रही हैं, उस नारी की शक्ति को, उसके महत्व को ब्रह्माकुमारी मिशन के संस्थापक ब्रह्मतुल्य प्रजापिता ने कई दशक पूर्व आंक लिया था। आपकी इस संस्था में 35 या पचास नहीं, बल्कि शत–प्रतिशत आरक्षण नारी शक्ति के लिये कब का हो चुका। आपके प्रणेता जी ने भारतीय संस्कृति के संदेश : यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः को पहले ही आत्मसात ? कर लिया।

विश्व शांति और इसमें मीडिया की भूमिका विषय पर फिर लौटते हैं। परिवारों से लेकर समाज तक और समाज से लेकर विश्व तक को शांति की माला में पिरोने के लिये निश्चय ही मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है, विश्व शांति के लिये जनमत तैयार कर सकता है और इस तरह जागरूक हुआ जनमत दुनिया के नीति–नियंताओं से यह सवाल कर सकता है कि आखिर शांति के लिये बनाये गये संगठन अपना फर्ज अदा क्यों नहीं कर पा रहे। कौन सी शक्तियां हैं, जो इन संस्थानों को पंगु बना रही हैं। दुनिया के मठाधीशों से पूछा जाना चाहिये कि वैश्विक भाईचारा और विश्व शांति के उद्देश्य से बनाये गये संगठनों, मसलन– संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, जी–ट्वेंटी, जी–सेवन, ब्रिक्स और ब्राड के होते हुए अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियां, इस्राइल और आतंकी शक्तियां मानवता को रौंदने पर क्यों तुली हैं?

अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय मीडिया के मेरे साथियों, उठाओ अपना गांडीव रूपी कलम का अस्त्र, दागो। अरे विश्व शांति के मसीहा का ढोंग रचने वाले महाशक्तिमानो, आप किस हैसियत से नोबेल शांति पुरस्कार पाने की जुगतें भिड़ा रहे हैं। मीडिया के शक्तिमानो जतला दो उन्हें कि कभी न कभी शांति का उजाला उनके झूठ के अंधकार को अवश्य निगल जायेगा। ऐसे हथियार विक्रेताओं को एक शायर की यह आवाज सुना दो :– तिरे चराग़ अलग हों मिरे चराग़ अलग, मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता।

मीडिया के मेरे दोस्तो, यह सच्चाई हमें माननी पड़ेगी कि सूचना की गति भले तेज हुई है, मगर संवेदना की गहराई कम हो रही है। मानवता के कल्याण के लिये हमें भी ब्रह्माकुमारी मिशनरियों की भांति शांति दूत की भूमिका निभानी होगी। मीडिया समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शक भी है। मीडिया की ताकत पर किसी शायर ने ठीक ही कहा है :–लफ्जों से ही बनते हैं रिश्तों के कारवां, मीडिया चाहे तो जोड़ दे जहां।

इसलिए आज पीत पत्रकारिता की नहीं, बल्कि पीस पत्रकारिता की जरूरत है। युद्ध की तस्वीरें जरूरी हैं, मगर शांति–वार्ता की मेज की तस्वीरें उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। महात्मा गांधी, बुद्ध, दादी प्रकाशमणि जी जैसे शांति दूतों के संदेश भी मीडिया की सुर्खियां बनें। याद रखिये, सरहदें नहीं रोक सकतीं संवेदनाओं का सैलाब। देश, धर्म, जाति चाहे अलग–अलग हों, दर्द सबका एक सा है। आंसू सबके एक से हैं। खून सबका एक सा है।

ब्रह्माकुमारी दीदी अक्सर कहती हैं, ह्यविचारोंह्ल से संसार बनता है। मीडिया विचारों का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि मीडिया ठान ले तो चौबीस घंटे में पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। ब्रह ?माकुमारी मिशन हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। वैश्विक शांति के लिये मीडिया को संक्षेप में ये चार सूत्र देते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। एक–संवाद को संघर्ष पर प्राथमिकता दें। दो–संवेदनशील मुद्दों को संतुलित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करें। तीन– सकारात्मक न्यूज स्टोरीज को प्रमुखता दें और अंत में चार–आध्यात्मिक मूल्यों करुणा, सहिष्णुता और मानवता को मंच प्रदान करें। ओम शांति।

सुशासन तिहार : उज्ज्वला गैस कनेक्शन, खत्म हुआ लकड़ी के चूल्हे का संघर्ष

नई दृष्टिबिंदु / कोरबा

सुशासन तिहार ने ग्राम धनरास की गृहिणी माधुरी के जीवन में नई रोशनी भर दी है। वर्षों से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की मजबूरी झेलती आ रही माधुरी आज बेहद खुश है, क्योंकि शिविर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें नि:शुल्क गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा प्रदान किया गया है।

गर्मी, धुआँ और हर दिन लकड़ी जुटाने की चिंता माधुरी के लिए हमेशा से एक बड़ी परेशानी रही। दो छोटे बच्चों और मजदूरी करने वाले पति की देखभाल के बीच लकड़ी से चूल्हा जलाना उनके लिए थका देने वाला काम बन गया था। गैस कनेक्शन के लिए उन्होंने कई बार पैसे जोड़े, लेकिन पूरी राशि एक साथ जमा न कर पाने के कारण वह गैस कनेक्शन नहीं ले पाई।

माधुरी ने बताया कि उनके गाँव धनरास में सुशासन तिहार के तहत शिविर लगने वाली है। शिविर में ग्रामीण अपना आवेदन देकर शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें यह भी जानकारी मिली कि शिविर में आवेदन देकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस जानकारी के बाद माधुरी ने तुरंत आवेदन दिया। आवेदन की जांच के उपरांत खाद्य विभाग द्वारा उनका चयन किया गया और उन्हें शिविर में गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए बुलाया गया।

शिविर में उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्वयं माधुरी को गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा प्रदान किया। गैस चूल्हा मिलने के बाद माधुरी ने बताया कि लकड़ी का चूल्हा जलाना उनके लिए बेहद कठिन था और अब गैस मिलने से खाना बनाना बहुत आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि दो छोटे बच्चों और मजदूरी करने वाले पति के लिए कभी भी तुरंत चूल्हा जलाकर भोजन बनाना मुश्किल था, लेकिन अब केवल लाइटर ऑन करने भर से खाना–नाश्ता आसानी से तैयार हो जाएगा।

माधुरी को यह गैस कनेक्शन पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान किया गया है। साथ ही 100 दिन का रोजगार पूरा करने पर उन्हें जॉब कार्ड भी दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और मजबूत हुई है। शिविर में कलिता बाई पति भरत लाल, ग्राम धनरास और नंदिनी वैष्णव पति अशोक कुमार, ग्राम धनरास को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और चूल्हा प्रदान किया गया। दोनों महिलाओं ने गैस मिलने पर राहत व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की योजना से उन्हें असल लाभ प्राप्त हुआ है और सुशासन तिहार जैसे कार्यक्रम ग्रामीण हितग्राहियों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रहे हैं।

नए जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम का निर्माण

एस. कृष्णन

ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करने की दिशा में भारत की पहल अवसर और जोखिम के संगम से उत्पन्न हुई है। बीते एक दशक में डिजिटल गेमिंग का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसे बड़े पैमाने पर स्माटफोन अपनाने, किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीक का उपयोग करने और उस पर निर्भर रहने वाली युवा आबादी का समर्थन मिला है। इस विकास ने नवाचार, कौशल विकास, रचनात्मक उद्योगों और रोजगार सृजन के लिए सार्थक अवसरों का सृजन किया है। मनोविनोद के लिए गेमिंग और संगठित प्रतिस्पर्धी प्रारूपों ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता भी प्रदर्शित की है।

इन अवसरों के साथ–साथ, ऑनलाइन मनी गेमिंग—विशेष रूप से सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले (यानी बेटिंग वेजरिंग) प्लेटफॉर्मों के अनियंत्रित विस्तार ने गंभीर सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को भी जन्म दिया। ऐसे अनेक सेवा प्रदाता राज्य सीमाओं के पार या विदेशी क्षेत्रों से संचालित होते थे, जो घरेलू सुरक्षा उपायों को नज ?अंदाज करते थे और कानूनों को लागू करना कठिन बनाते थे। दबाव बनाने वाले विज्ञापनों और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाले डिजाइन फीचर्स ने कमजोर उपयोगकर्ताओं में लत जैसी प्रवृत्तियों और वित्तीय नुकसान को बढ़ावा दिया। वित्तीय संकट, डिजिटल भुगतान प्रणालियों के दुरुपयोग और अस्पष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन–देन की रिपोर्ट्स ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को उजागर किया। इन परिस्थितियों ने एक ऐसे राष्ट्रीय ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो व्यक्तियों—विशेषकर युवाओं—की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए गेमिंग इकोसिस्टम के वैध हिस्सों को जिम्मेदारी से विकसित होने में सक्षम बनाए।

ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई–स्पोर्ट्स नामक संगठित प्रतिस्पर्धी प्रारूपों जैसे वैध गेमिंग क्षेत्रों की सहायता के लिए एकीकृत संस्थागत ढाँचे का अभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। डेवलपर्स के पास श्रेणीकरण की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, जिसका पहले से अनुमान लगाया जा सके और उपयोगकर्ताओं को अक्सर वैध मनोरंजन और अवैध सट्टेबाजी के बीच फर्क समझने में कठिनाई होती थी। अतः इसका उद्देश्य केवल हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि एक संतुलित ढाँचा भी स्थापित करना था, जो उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जिम्मेदार नवाचार को भी संभव बनाए।

ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025, (पीआरओजीए) इसी संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे डेवलपर्स, ई–स्पोर्ट्स संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी पेशेवरों और सामाजिक संगठनों के हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं में लगातार पारदर्शी श्रेणीकरण, पूर्वानुमेय अनुपालन दायित्वों और वैध प्रारूपों के लिए व्यवस्थित व सरल मान्यता प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हितधारकों ने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई मजबूत करते हुए वैध मनोरंजक और प्रतिस्पर्धी गेमिंग को बढ़ावा देने का समर्थन किया।

संचालन स्तर पर, यह ढाँचा परस्पर संबद्ध तीन चरणों—अवधारण, मान्यता और पंजीकरण—पर आधारित एक व्यवस्थित श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये चरण क्रमिक रूप से कार्य करते हैं और इन्हें पीआरओजीए तथा उसके नियमों में दी गई वैधानिक परिभाषाओं के साथ समझना आवश्यक है।

अवधारण एक नियामक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से किसी भी गेम की जांच और उसका श्रेणीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक ऑनलाइन गेम के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल सीमित और निर्धारित परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ई–स्पोर्ट्स की मान्यता से पहले अवधारण अनिवार्य होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्पर्धी प्रारूप वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं और सट्टेबाजी के तत्वों से मुक्त रहते हैं। इसके अलावा, अवधारण आमतौर पर उन स्थितियों में आवश्यक होता है, जब किसी गेम के ऑनलाइन मनी गेमिंग की परिभाषा के दायरे में आने की आशंका हो, जब अधिसूचित ऑनलाइन सोशल गेम्स की श्रेणियों के लिए श्रेणीकरण जरूरी हो, जब शिकायतों या खुफिया सूचनाओं से प्रतिबंधित गतिविधियों को सक्षम करने वाले संभावित वित्तीय तत्वों का संकेत मिले, या जब भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (ओजीएआई) जनहित में जांच का निर्देश दे। अवधारण प्रारंभिक श्रेणीकरण को संभव बनाकर, अवैध वित्तीय मॉडलों को गेमिंग इकोसिस्टम में प्रवेश करने से रोकता है, जबकि वैध प्रारूपों को नियामक स्पष्टता के साथ आगे बढ ? की अनुमति देता है।

अवधारण के बाद, पात्र प्रारूपों को मान्यता दी जा सकती है। ई–स्पोर्ट्स की मान्यता राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के अंतर्गत विनियमित होती है, जिसमें संगठित मल्टीप्लेयर गेमप्ले, पूर्व–निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक नियम और परिणाम केवल मानसिक कौशल, शारीरिक दक्षता या रणनीतिक निर्णय लेने जैसे कारकों पर आधारित होना आवश्यक है। प्रतिभागिता शुल्क की अनुमति केवल प्रतियोगिता से संबंधित प्रशासनिक खर्चों और प्रदर्शन–आधारित पुरस्कार संरचनाओं को समर्थन देने के लिए ही दी जा सकती है। हालांकि, किसी भी रूप में सट्टेबाजी या दांव लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। मान्यता से पहले अनिवार्य अवधारण यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त ई–स्पोर्ट्स प्रारूप सभी वैधानिक सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं।

इसके समानांतर, यह ढाँचा ऑनलाइन सोशल गेम्स के पंजीकरण के लिए एक मार्ग स्थापित करता है, जो वित्तीय सट्टेबाजी के लिए नहीं, बल्कि मुख्यतः मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता के उद्देश्य से बनाए गए होते हैं। ऑनलाइन सोशल गेम्स की केवल उन्हीं श्रेणियों का ही पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया हो। जहाँ श्रेणीकरण की निश्चितता होना आवश्यक है, वहाँ पंजीकरण से पहले अवधारण किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें सट्टेबाजी के तत्व मौजूद नहीं हैं।

इस श्रृंखला का अंतिम चरण पंजीकरण है, जो नियामक दृश्यता प्रदान करता है तथा संतुलित निगरानी और लागू की जा सकने वाली जवाबदेही सुनिश्चित करता है। पंजीकरण आमतौर पर ई–स्पोर्ट्स की मान्यता के बाद होता है या फिर ऑनलाइन सोशल गेम्स की अधिसूचित श्रेणियों पर लागू होता है। यह उन मामलों में भी निर्देशित किया जा सकता है, जहाँ निर्धारण के परिणाम औपचारिक निगरानी की आवश्यकता दर्शाते हैं या जहाँ ओजीएआई जनहित में ऐसी निगरानी को आवश्यक समझता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकरण पूरे प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि प्रत्येक ऑनलाइन गेम सेवा प्रदाता के अलग–अलग खेलों पर लागू होता है, जिससे अनुपालन यथोचित बना रहता है और साथ ही प्राधिकरणों को अधिकृत खेलों का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायता मिलती है।

यह वर्तमान ढाँचा प्रतिक्रियात्मक प्रवर्तन से आगे बढ़कर सक्रिय और निवारक शासन की ओर परिवर्तन दर्शाता है। अनुकूल अवधारण प्रारंभिक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, मान्यता वैधता का स्पष्ट फर्क स्थापित करती है, और पंजीकरण नियामक दृश्यता प्रदान करते हुए सही निगरानी और लागू की जा सकने वाली जवाबदेही सुनिश्चित करता है। साथ ही, अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ कार्यान्वयन को, विशेष रूप से विदेशी ऑपरेटरों को लक्षित करते हुए समन्वित ब्लॉकिंग, जांच–आधारित ओजीएआई की कार्रवाई और वित्तीय व्यवधान के उपायों के माध्यम से मजबूत किया गया है। यह दो–स्तरीय दृष्टिकोण ढाँचे की मूल विचारधारा: वैध संस्थाओं के लिए हल्के फुल्के नियमन तथा अवैध संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यान्वयन को प्रतिबिंबित करता है।

कार्यान्वयन के अलावा, यह ढाँचा जिम्मेदार इकोसिस्टम के विकास के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करता है। स्पष्ट नियामक मार्ग वैध गेमिंग के विकास, प्रतिस्पर्धी अवसंरचना और सहायक डिजिटल सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। ई–स्पोर्ट्स की मान्यता संगठित प्रतियोगिताओं और पेशेवर भागीदारी को सक्षम बनाती है, जबकि विनियमित श्रेणियाँ विकास, अनुपालन, साइबर सुरक्षा और इवेंट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों में सहायता देती हैं।

पीआरओजीए के माध्यम से शुरू किया गया यह परिवर्तन बिखरी हुई प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर पूर्वानुमेय शासन की ओर बदलाव को दर्शाता है। निवारक श्रेणीकरण, वैध मान्यता और जवाबदेह पंजीकरण को एक साथ जोड़कर यह ढाँचा एक स्थिर वातावरण तैयार करता है, जहाँ नवाचार जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदारी के साथ विकसित हो सकता है।

(लेखक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव है।)

अधिकारों का सार्थक ढंग

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि भारत में समस्या अधिकारों का अभाव नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारों का सार्थक ढंग से उपभोग किया जा सके। भारत की जमीनी हकीकत से परिचित लोग सहज ही इस राय से इत्तेफाक रखेंगे।

अधिकारों पर जारी बहस के बीच प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने यह महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की है कि 'जिस अधिकार का व्यवहार में उपभोग ना किया जा सके, वह कागजी वायदे के ज्यादा कुछ नहीं है।इ उन्होंने कहा कि भारत में समस्या अधिकारों का अभाव नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारों का सार्थक ढंग से उपयोग किया जा सके। भारत की जमीनी हकीकत से परिचित लोग सहज ही प्रधान न्यायाधीश की इस राय से इत्तेफाक रखेंगे। बेशक, अपने देश में नागरिकों के लिए संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की लंबी सूची है। मगर ये कड़वी हकीकत है कि अधिकांश नागरिकों के लिए वे अधिकार ज्यादा मायने नहीं रखते।

मसलन, जिन नागरिकों को उपयुक्त शिक्षा–दीक्षा और ऐसी परिस्थितियां प्राप्त नहीं हुईं, जिनसे वे राजकाज एवं सार्वजनिक मुद्दों पर कुछ कहने योग्य विचार विकसित कर पाएं, उनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी महज ऐसा गहना है, जिसे वे कभी पहन नहीं पाते। फिर आसपास भयमुक्त वातावरण ना हो, तो उनके इस अधिकार के लिए खतरा सिर्फ सरकार के फरमानों से नहीं, बल्कि स्थानीय सामाजिक–आर्थिक ढांचे से भी पैदा होता है। जस्टिस कांत ने भी कहा कि भौगोलिक स्थितियों, इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी कमियों और आर्थिक बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग अदालत और उन संस्थाओं के पास नहीं पहुंच पाते, जिनका मकसद उनके अधिकारों की रक्षा है।

सार यह कि अधिकारों का विमर्श तभी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, जब अधिकारों के उपभोग की परिस्थितियों को चर्चा में शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अधिकारों के हनन की सारी बहस सभ्रांत वर्ग के दायरे में सिमटी रहती है। संभवतः यही कारण है कि नागिरक अधिकारों पर हमले और संविधान बचाओ जैसी बातें आम जन मानस को नहीं छू पातीं। जो तबके ऐसे अधिकारों से वंचित हैं, उनमें वोट की ताकत उन हकों की रक्षा करने का जज्बा गायब रहता है। उलटे नकदी ट्रांसफर की योजनाएं उन्हें लुभा लेती हैं, क्योंकि उनसे भले ही सीमित, लेकिन वास्तविक फायदा उन्हें मिलता है। अतः जस्टिस कांत की टिप्पणियों को उनकी सही भावना में देखा जाना चाहिए। ऐसा करना अधिकारों को उनके असल संदर्भ में देखना होगा।

सही दवा, शुद्ध आहार अभियान के तहत सघन जांच, अस्पतालों व फार्मेसी की कोल्ड चेन व्यवस्था पर फोकस

राज्य शासन के निर्देश पर 15 दिवसीय विशेष अभियान जारी, मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के संकेत

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सही दवा, शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले स्तर पर संचालित यह अभियान 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक जिलेभर में निरंतर जारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त एवं मानक अनुरूप खाद्य सामग्री एवं औषधियां उपलब्ध कराना है।

इसी कड़ी में 1 मई को रायगढ़ शहर के विभिन्न अस्पतालों एवं उनसे संबद्ध फार्मेसी प्रतिष्ठानों में वैक्सीन स्टोरेज की कोल्ड चेन व्यवस्था का विशेष निरीक्षण एवं सघन जांच की गई। जांच के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया गया।

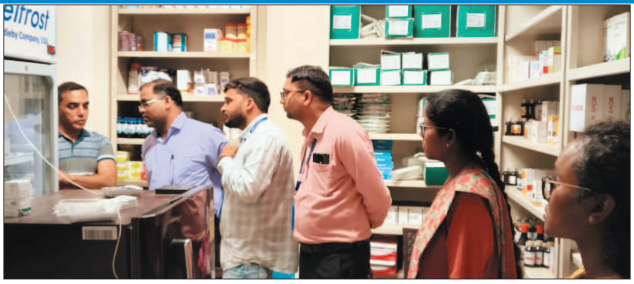

कार्यवाही के अंतर्गत अपेक्स फार्मेसी (छातामुड़ा बायपास), गोयल फार्मेसी (छातामुड़ा), श्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल (लोचन नगर) एवं मेट्रो हॉस्पिटल, रायगढ़ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण, निर्धारित तापमान के अनुरक्षण, कोल्ड चेन की सतत निगरानी, स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण प्रणाली की विस्तार से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा कोल्ड चेन प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभियान अवधि के दौरान यदि कहीं भी अनियमितता या मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा संचालित इस अभियान के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, बल्कि आमजन के बीच सुरक्षित दवा और शुद्ध आहार के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे दवा एवं खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता और प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जनगणना-का शंखनाद : शुरू हुआ घर-घर सर्वेक्षण कार्य

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

भारत की जनगणना- 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण यानी "मकान सूचीकरण और मकानों की गणना" का कार्य आज से जिले में औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। इस महाअभियान के सफल संचालन हेतु 1300 से अधिक प्रगणक एवं सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो 1 मई से 30 मई तक घर-घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। गौरतलब है कि इतिहास में पहली बार जनगणना पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसे प्रगणक अपने मोबाइल ऐप के जरिए संपन्न करेंगे। वहीं, जनसंख्या गणना का द्वितीय चरण मार्च 2027 में आयोजित किया जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ाया उत्साह

तहसील कार्यालय सारंगढ़ पहुँचकर जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे एवं जिला जनगणना अधिकारी डिप्टी कलेक्टर उमेश कुमार साहू एवं चार्ज अधिकारी तहसीलदार नरेंद्रसिंह सिन्हा ने प्रगणकों को पुष्प भेंट किए और उन्हें फील्ड कार्य के लिए रवाना किया।

इस अवसर पर कलेक्टर ने प्रगणकों को निर्देशित किया कि वे सर्वे के दौरान डेटा की गुणवत्ता और सटीकता का विशेष ध्यान रखें और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करें।

भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष सावधानी की सलाह

जिले में पड़ रही अत्यधिक गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने प्रगणकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी है। उन्होंने फील्ड के दौरान सीधे धूप से बचने और अपने साथ पर्याप्त पानी एवं ओआरएस रखने को कहा है।

नागरिकों से की अपील

प्रशासन ने जिलेवासियों से भावपूर्ण अपील किया है कि जब भी प्रगणक आपके घर पहुँचें, तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। यह एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसमें हर नागरिक की सही जानकारी राष्ट्र के उन्नति के लिए भविष्य की योजनाओं के निर्माण में सहायक होगी।

बाल हितैषी पंचायत में कछिया ने बनाया कीर्तिमान

शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में जनभागीदारी से मिली ऐतिहासिक उपलब्धि, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब राज्य स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित पहलों के बीच जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के जनपद पंचायत वाड्रफनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत कछिया ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

ग्राम पंचायत कछिया ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के तहत पीएआई 2.0 सर्वे के 9 थीम में से थीम-3 (बाल हितैषी पंचायत) में 95.71 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बन गई है।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्राम पंचायत कछिया के जनप्रतिनिधियों, पंचायत अमले और ग्रामीणों को बधाई देते हुए इसे राज्य के अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणादायक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता सबका साथ, सबका विकास की भावना और जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल का उत्कृष्ट उदाहरण है।

ग्राम पंचायत कछिया ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक समग्र बाल हितैषी वातावरण विकसित किया है। पंचायत के प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में कुल 155 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें बालिकाओं की संख्या उल्लेखनीय है। पंचायत द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा, विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने, स्वच्छता सुधार, पोषण और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विद्यालयों का नियमित निरीक्षण, स्कूल प्रबंधन समिति के साथ समन्वय, स्वच्छता अभियान, सुरक्षित पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य जागरूकता, तथा ग्रामसभा में बच्चों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना इस सफलता के प्रमुख आधार रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ समन्वय कर एनीमिया मुक्त पंचायत, शत-प्रतिशत टीकाकरण और मातृ-पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रारंभिक चरण में पलायन, आर्थिक स्थिति और जागरूकता की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। पंचायत ने घर-घर संपर्क, अभिभावक संवाद, नियमित समीक्षा बैठकें और सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया। ग्राम पंचायत ने बाल हितैषी गतिविधियों को स्थायी रूप देने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें शत-प्रतिशत नामांकन, शून्य ड्रॉपआउट, नियमित मॉनिटरिंग, स्वच्छता अभियान और बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की दोहरी उपलब्धि

फाइलेरिया व मलेरिया नियंत्रण में राज्य मॉडल की देशभर में हो रही सराहना

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। 30 अप्रैल और 01 मई 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित "National Summit on Innovation and Inclusivity – Best Practices Shaping India's Future" में राज्य को फाइलेरिया और मलेरिया उन्मूलन के लिए अपनाई गई नवाचारी पहलों पर सम्मानित किया गया।

यह सम्मान न केवल राज्य की स्वास्थ्य रणनीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, बल्कि सामुदायिक भागीदारी आधारित मॉडल की सफलता का भी प्रमाण है।

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में इक्कठअठ (स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन) से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। Mission Steering Group–Human Resource (MSG–HR) के अंतर्गत इस मॉडल को देश की सर्वश्रेष्ठ नवाचारी और समावेशी पहल के रूप में मान्यता मिली, जिसमें ढकक्क्र्ह का तकनीकी सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा।

मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के दौरान महिलाओं ने घर-घर पहुंचकर न केवल दवा सेवन सुनिश्चित कराया, बल्कि समुदाय में व्याप्त भ्रांतियों को भी दूर किया। सामुदायिक बैठकों और जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों में भरोसा कायम किया गया। इसका परिणाम यह रहा कि दवा सेवन से इनकार करने वाले लगभग 74% लोगों को सहमति के लिए तैयार किया गया-जो इस मॉडल की सबसे बड़ी सफलता के रूप में उभरकर सामने आया।

सम्मेलन में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को भी एक प्रभावी और परिणामोन्मुख पहल के रूप में विशेष सराहना मिली। बस्तर के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में संचालित इस अभियान के तहत घर-घर स्क्रीनिंग, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से समय पर जांच, त्वरित उपचार और Day-7 व Day-14 फॉलो-अप के माध्यम से पूर्ण इलाज सुनिश्चित किया गया। इस अभियान की खास उपलब्धि लक्षणहीन मरीजों की पहचान रही, जिससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में निर्णायक मदद मिली। इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट रूप से सामने आए हैं- राज्य का अक्कवर्ष 2019 में 1.97 से घटकर 2025 में 0.90 हो गया, जबकि बस्तर संभाग में यह 13.12 से घटकर 6.98 तक पहुंच गया।

राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं ने छत्तीसगढ़ के इक्कठअठ आधारित सामुदायिक मॉडल और ह्ममलेरिया मुक्त बस्तरह्न अभियान को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। कम लागत में अधिक प्रभाव देने वाली ये पहलें यह साबित करती हैं कि जनभागीदारी और स्थानीय रणनीतियों के माध्यम से जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान संभव है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी समुदाय आधारित, नवाचारयुक्त और क्षेत्र विशेष रणनीतियों को प्राथमिकता देते हुए, जनस्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा

भीषण गर्मी में गरियाबंद के गांवों को मिलेगी राहत, एक सप्ताह नहर से मिलेगा पानी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और ग्रामीणों की मांग को देखते हुए। जल संसाधन विभाग ने निस्तारी के लिए पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि 15 अप्रैल 2026 को सिकासार जलाशय से जल प्रवाह बंद कर दिया गया था। इस पर राजिम विधायक रोहित साहू से चर्चा के बाद विभाग ने पुनः पानी छोड़ने का फैसला लिया। 1 मई 2026 से एक सप्ताह के लिए फिंगेश्वर वितरक शाखा नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्राम बेलर, बोड़की, जोगीडिपा और पतोरी घोघरा के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। कुछ तालाबों को खेतों के रास्ते पानी पहुंचाकर भरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि इस दौरान खेतों में पानी जाने से किसी फसल को नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी, न कि जल संसाधन विभाग की। साथ ही ग्रामीणों और किसानों से पानी का उपयोग सही से करने की अपील की है।

बस्तर मुन्ने और सुशासन तिहार : जिला पंचायत सीईओ ने लगाई चौपाल

नई दृष्टिबिंदु / कांकेर

सुशासन तिहार और बस्तर मुन्ने अभियान के प्रथम दिवस जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी ने आज कोयलीबेड़ा विकासखंड के सुदूरवर्ती सरहदी ग्राम पंचायत कंदाड़ी में कोटरी नदी को पार करके पहुंचे, जहां पर आयोजित शिविर में उन्होंने आम पेड़ के नीचे ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनीं। कभी अतिसंवेदनशील इलाके के तौर पर जाने जाने वाले इस ग्राम के ग्रामीणों ने पहली बार आला अधिकारी को अपने बीच पाकर काफी प्रसन्नता जाहिर की।

इस दौरान जिला सीईओ श्री मंडावी ने बताया कि बस्तर मुन्ने, सुशासन तिहार और नियद नेल्लानार योजना 2.0 में पूरे कोयलीबेड़ा ब्लॉक को शामिल किया गया है और प्रदेश सरकार की मंशानुसार कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन द्वारा अधिसूचित 31 योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि जब तक प्रत्येक पात्र हितग्राही को इसका लाभ नहीं मिल जाता, तब तक शिविर लगाकर इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से सिलसिलेवार उनकी समस्याएं और मांगों की जानकारी ली।

ग्राम पंचायत कंदाड़ी की सरपंच श्रीमती मैनी कचलामी ने बताया कि ज्यादातर ग्रामीण आधार, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में नामों में विसंगतियां होने के कारण अनेक योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांगों में पेयजल, सीसी रोड निर्माण और आश्रित ग्राम आलदंड की प्राथमिक शाला भवन के जर्जर होने पर किचन शेड और अतिरिक्त भवन स्वीकृत करने और मिडिल स्कूल कंदाड़ी में बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की। इस दौरान जिला सीईओ ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र भवन आलदंड का निरीक्षण किया, जिसे 11.69 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है।

होनहार छात्रा कु अमिला से की भेंट

इस दौरान वे ग्रामीण आयतु नरेटी के घर पहुंचे, जहां उनकी पुत्री कु. अमिला नरेटी से भेंट की। पूछने पर पता चला कि वह बीएससी 71 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण है और आगे एमएससी की पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इस पर सीईओ ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद करने की बात कही।

जिला सीईओ श्री मंडावी ने इसके पश्चात महाराष्ट्र के सीमावर्ती ग्राम ओरछा गांव (गोपालपुर) में आयोजित शिविर में हिस्सा लिया। पंचायत सचिव के द्वारा ग्रामीणों को बस्तर मुन्ने कार्यक्रम में सम्मिलित 31 योजनाओं की जानकारी नहीं दे पाने पर नाराजगी जताते हुए पूरी जानकारी के साथ गाँव में फिर से शिविर लगाने के निर्देश जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के सीईओ उदय नाग को दिए। साथ ही ग्रामीणों से समस्याओं के बारे में पूछा, जिस पर ग्राम पंचायत ओरछा गांव की सरपंच श्रीमती सविता गोटा ने बिजली के लो-वोल्टेज और पेयजल की समस्या दूर करने और स्कूल मार्ग पर सीसी रोड निर्माण करने की मांग की, जिस पर उन्होंने समुचित कार्रवाई करने की बात कही। श्री मंडावी ने महाराष्ट्र की सीमा से लगी नदी का अवलोकन भी किया।

महासमुंद में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों का किया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / महासमुंद

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर महासमुंद के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री रवि साहू सहित श्रम विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में श्रमिक साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सफाई कर्मी, मिशन क्लीन सिटी से जुड़े श्रमिक, भूमिहीन किसान मजदूर सहित विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

श्रमिक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं श्रम न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरूआत एक मई 1886 से मानी जाती है जब अमेरिका की मजदूर युनियनों ने काम का समय 8 घंटे से अधिक ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में एक मई का दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर प्रमाणित कर लिया गया था। इसकी

शुरुवात भारती मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगारावेलू चेटयार ने शुरू की थी। भारत में मद्रास के हाईकोर्ट सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और एक संकल्प पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में भी कामगार दिवस के तौर पर मनाया जाए और इस दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। इसके अलावा वेतन संहिता 2019 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि यह संगठित और असंगठित दोनों सेक्टर के सभी कर्मचारियों पर लागू नियमों, न्यूनतम वेतन नियम, समय पर वेतन, बोनस, समान काम समान वेतन, ओवर समय का वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं व्यवसायिक सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले विधिक सलाह एवं सहायता के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष देवी चंद राठी, श्री महेंद्र सिक्का, अपर कलेक्टर रवि साहू, श्रम पदाधिकारी डीएन पात्र, टास्क फोर्स समिति सदस्य श्रीमती प्रेमशीला बघेल, विधायक प्रतिनिधि रेखा बेहरा सहित श्रम विभाग के कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में श्रमिक साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सफाई कर्मी, मिशन क्लीन सिटी से जुड़े श्रमिक, भूमिहीन किसान मजदूर सहित विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष देवी चंद राठी ने श्रमिकों के योगदान को समाज और विकास की आधारशिला बताते हुए उनके कल्याण हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं की सराहना की। टास्क फोर्स समिति सदस्य श्रीमती प्रेमशीला बघेल ने अपने संबोधन में श्रमिकों के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर बल दिया। वहीं श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र ने श्रम विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए श्रमिकों से इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया।

इस अवसर पर श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तचाप, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य जांचें की गई तथा आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने श्रमिकों के साथ बैठकर सामूहिक भोजन किया। कार्यक्रम में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करते हुए उनके अधिकारों एवं कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।

श्रमिकों को गमछा वितरित

भिलाई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस (1 मई) के अवसर पर दुर्ग शहर में श्रमिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का संदेश देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा, दुर्ग द्वारा विशेष पहल की गई। महापौर अल्का बाघमार के निर्देशानुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर मजदूरों को धूप से बचाव के लिए गमछों का वितरण किया गया।

भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर मजदूरों को गमछे वितरित किए और उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष उल्लेख साहू, मंत्री उमंग ताम्रकार सहित राहुल सिंह, निखिल शर्मा, आर्यश राजपूत, साहिल चंद्राकर, प्रतीक, तन्मय और प्रभात तिवारी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे।

मुझसे अच्छे कई कलाकारों की किस्मत ने साथ नहीं दिया

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चाओं में हैं। फिल्म सिनेमाघरों में बनी हुई है। हाल ही में अक्षय कुमार का कहना है कि सफलता के लिए मेहनत जरूरी होती है। लेकिन मेरे करियर में मेहनत से ज्यादा भाग्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं अभिनेता अपने फिल्मी सफर को लेकर भी बात की।

मैं लगन से करता हूं मेहन

क्विज रियलिटी शो 'व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून' को होस्ट कर रहे अक्षय कुमार ने मेहनत और भाग्य को लेकर अपनी राय रखी। शो में अक्षय ने कहा कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर ऐसा मानता हूं कि मेहनत की जरूरत तो है और मैं पूरी लगन से मेहनत करता हूं। लेकिन मेरे करियर में या मेरी जिंदगी में भाग्य ने ज्यादा काम किया है। हजारों ऐसे कलाकार मिलते हैं, जिनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया

अक्षय कुमार ने फिल्म सेट पर अपने रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर आगे बताया कि उन्हें नियमित रूप से हजारों ऐसे युवा, महत्वाकांक्षी अभिनेता मिलते हैं जो उनसे अधिक प्रतिभाशाली या दिखने में बेहतर होते हैं। लेकिन फिर भी गुमनाम रह जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया है।

तीन दशकों से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं अक्षय

अक्षय कुमार तीन दशकों से अधिक समय से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और अब उनकी गिनती इंडस्ट्री के टॉप लीडिंग स्टार्स में होती है। उन्होंने लगभग 150 से भी अधिक फिल्में की हैं। इनमें कई ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में रही हैं। इनमें 'हेरा फेरी', 'केसरी', 'जॉली एलएलबी', 'हाउसफुल' और 'खिलाड़ी' सीरीज जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। अक्षय की पाइपलाइन में हैं ये बड़ी फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय की 'भूत बंगला' इन दिनों सिनेमाघरों में बनी हुई है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म से अक्षय और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी ने 14 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

आज की युवा पीढ़ी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की शिकार

आज की तेजी से बदलती दुनिया और तकनीक के विस्तार ने युवाओं की जीवनशैली को पूरी तरह से बदल दिया है। अवसर सोशल मीडिया पर अपने अनोखे रिलेशनशिप ट्रेंड्स और नए 'स्लैंग' के कारण चर्चा में रहने वाली जेनजी को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने अपने विचार शेयर किए। गुरुवार को अभिनेत्री ने एक पॉडकास्ट का विलप इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसमें काजोल ने अपनी और जेनजी के बीच की बुनियादी अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया कि कैसे जानकारी की अधिकता आज की युवा पीढ़ी के लिए चुनौती बन गई है। उनका मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को इंटरनेट से मिलने वाले 'शोर' से बाहर निकलकर खुद के लिए फैसला लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। केवल सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना काफी नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों और सीमाओं को खुद परिभाषित करना ही असल परिपक्वता है। काजोल कहती हैं, 'मुझे लगता है कि जेनजी इस समय 'जानकारी के ओवरलोड' से गुजर रही है। हम ऐसे समय में बड़े हुए जब जानकारी बहुत सीमित हुआ करती थी। इसलिए हमें अपनी नैतिकता, सीमाएं और सही-गलत का फैसला खुद अपनी सोच से करना पड़ता था।' अभिनेत्री ने बताया कि आज के युवाओं के पास हर चीज के बारे में जवाब उपलब्ध हैं। हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलता, लेकिन वे इसमें इस कदर खोए हुए हैं कि वे यह तय नहीं कर पा रहे कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या सही है। उन्होंने कहा, 'आप चाहे जितनी भी चिंता कर लें या जानकारी जुटा लें, लेकिन आखिर में आपको अपना मन खुद ही बनाना होगा।' अभिनेत्री ने अपने दोनों बच्चों बेटी निसा देवगन और बेटा युग देवगन को लेकर कहा कि दोनों के नजरिए अलग हैं। उन्होंने कहा, 'मेरे दोनों बच्चे अपनी जानकारी अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। मुझे लगता है कि लड़कों की जिंदगी अक्सर थोड़ी ज्यादा सीधी-सादी होती है। वे सूचनाओं को सरलता से लेते हैं, लेकिन लड़कियों पर समाज, सोशल मीडिया और सूचनाओं का दबाव या बोझ कहीं ज्यादा होता है। उन्हें कई पैमानों पर खुद को परखना पड़ता है।'

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' की रिलीज डेट में हुआ बदलाव; टॉक्सिक से होगा मुकाबला

बॉबी देओल अपनी आगामी फिल्म 'बंदर'/ 'मंकी इन अ केज' को लेकर चर्चा में हैं। बीते साल सितंबर में इसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इस साल फरवरी में फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया गया था। यह फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। मगर, अब दर्शकों को इसके लिए इंतजार करना होगा।

फिल्म 'बंदर' अब मई में नहीं, बल्कि जून में रिलीज होगी। दिलचस्प बात यह है कि सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से इसकी टक्कर होगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक फिल्म 'बंदर' 05 जून को दुनियाभर के थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। बता दें कि यश की मेगा बजट फिल्म 'टॉक्सिक' 04 जून, 2026 को रिलीज हो रही है।

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी, बॉबी देओल, सान्या मल्होत्रा, सबा आजाद और सपना पब्बी अभिनीत फिल्म 'बंदर' को निखिल द्विवेदी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर बीते साल जुलाई में रिलीज किया किया गया था। तब इस फिल्म का सलेक्शन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। अब यह फिल्म भारतीय दर्शकों तक पहुंच रही है।

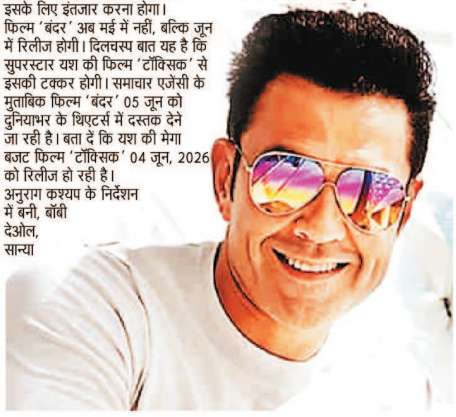

यामी गौतम ने इस फिल्म के लिए सीखी 'कुरान'

फिल्म निर्माता सुपन वर्मा और यामी गौतम ने हाल ही में साथ में एक फिल्म की थी। इस फिल्म को लेकर निर्देशन ने कई खुलासे किए हैं। साथ ही यह भी बताया कि इस फिल्म के लिए यामी गौतम को कुरान सीखनी पड़ी थी।

'हक' के लिए यामी ने सीखी कुरान?

फिल्म 'हक' नवंबर 2025 में रिलीज हुई थी। इसमें मुख्य भूमिकाओं में यामी गौतम और इमरान हाशमी हैं। इस फिल्म के लिए यामी ने कुरान पढ़ना सीखा था। सुपन वर्मा ने हाल ही में बीबीसी को बताया कि यामी ने अपनी भूमिका के लिए कुरान का अध्ययन किया था। फिल्म बनाने के लिए टीम ने इस्लामी कानून को समझने में डेढ़ साल का समय लगाया। सुपन ने आगे कहा कि आजकल 'गलत सूचनाओं का युग' है, इसलिए उन्होंने फिल्म में सही और तर्कसंगत जानकारी दिखाने की कोशिश की है। यामी गौतम ने भी फिल्म की अच्छी समीक्षाओं पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि लोगों की ईमानदार राय और सकारात्मकता उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। 'हक' 1970 के दशक की कहानी को दिखाती है। यामी गौतम ने शाजिया बानो नाम की एक वकील की पत्नी का रोल निभाया है। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें भरण-पोषण देने से मना कर दिया। इसके बाद शाजिया अदालत में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती हैं।

'हक' ओटीटी पर है उपलब्ध

40 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म 'हक' ने करीब 30 करोड़ रुपये ही कमाए। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह ज्यादा सफल नहीं हो पाई। सिनेमाघरों के बाद 'हक' ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म न्याय के मुद्दों पर आधारित है, जिसे अब नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।

सुपर कॉप के रोल में फिर तबाही मचाएंगे रणदीप हुड्डा

रणदीप हुड्डा स्टारर सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' का पहला सीजन 2023 में आया था। इसके बाद से ही फैंस इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। अब मेकर्स ने इसके दूसरे सीजन का टीजर रिलीज कर फैंस की धड़कनें और बढ़ा दी हैं।

क्या है टीजर में खास

टीजर में रणदीप हुड्डा दबंग इंस्पेक्टर के रूप में नजर आ रहे हैं। कुछ सीन में वे बहरूपिया भी बनते दिखाई दिए हैं। टीजर में काफी दमदार डायलोग्स बताए गए हैं। इनमें से एक है जिसमें रणदीप हुड्डा कहते हैं- 'जिंदगी और मृत्यु के बीच सिर्फ हमारी एक उंगली का फर्क है।' वहीं टीजर में कुछ इंटेंस सीन भी नजर आए हैं, जिनमें एक्टर दमदार एक्शन सीन करते नजर आए हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा- 'यूपी का महाकाल, इस्पेक्टर अविनाश वापस आ रहे हैं। और इस बार होगा असली तांडव।'

कब रिलीज होगी सीरीज

सीरीज में रणदीप के अलावा उर्वशी रौतेला, रजनीश दुग्गल, अमित सियाल, सरगम सिंह, शालीन भनोट अहम किरदार में नजर आएंगे। सीरीज का निर्देशन नीरज पाठक कर रहे हैं। फिलहाल मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है। सीरीज पिछले पार्ट से ज्यादा एक्शन पैक और इंटेंस बताई जा रही है। मेकर्स ने सीरीज के दूसरे सीजन 'इंस्पेक्टर अविनाश' का टीजर रिलीज कर दिया है। ये सीरीज हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

सारा अर्जुन की लगी लॉटरी, 'धुरंधर 2' की यलीना अब बनेगी मधुबाला

'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में यलीना के रोल से छाईं सारा अर्जुन अब मधुबाला बनेंगी। खबर है कि उन्हें मधुबाला की बायोपिक के लिए साइन किया गया है। नाम कन्फर्म है और एक्ट्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान बाकी है।

हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाने वालीं मधुबाला की बायोपिक की चर्चा कई साल से हो रही है। इसके लिए कई एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए, पर किसी पर भी मुहर नहीं लगी। अब इसके लिए 'धुरंधर' की यलीना यानी सारा अर्जुन का नाम कन्फर्म बताया जा रहा है। यानी उनकी लॉटरी लग गई है। कहा जा रहा है कि वह मधुबाला पर बन रही बायोपिक में उनका किरदार निभाएंगी। उनका नाम मधुबाला की बायोपिक के लिए कन्फर्म है। इस बायोपिक को जसमीत के रीन डायरेक्ट करेंगी, जबकि संजय लीला भंसाली प्रोड्यूसर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मधुबाला की बायोपिक की शूटिंग जुलाई 2026 से शुरू होगी। 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के बाद इसे सारा अर्जुन के करियर की अहम फिल्म माना जा रहा है, जो उनके करियर को एक नई दिशा देगी। सारा अर्जुन वैसे तो बचपन से फिल्मों में काम कर रही हैं, पर 'धुरंधर' ने उन्हें रातोंरात जबरदस्त स्टारडम दिलाया है।

इस कारण मधुबाला की बायोपिक में हुई देरी

मधुबाला की बायोपिक की बात करें, तो यह कई साल से अटकी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, बजट की कमी के कारण इसे कई बार देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में यह ट्रैक पर लौट आई। अहम मोड़ तब आया जब संजय लीला भंसाली बतौर प्रोड्यूसर मधुबाला की बायोपिक से जुड़े। वहीं जसमीत के रीन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने विजय वर्मा और आलिया भट्ट स्टारर 'डार्लिंग्स' डायरेक्ट की थी।

सारा ने शुरू की तैयारी

बताया जा रहा है कि सारा अर्जुन ने मधुबाला की खूबसूरती, गरिमा और पर्दे पर उनकी उपस्थिति को हूबहू उतारने के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। अब दिलीप कुमार और किशोर कुमार के किरदारों के लिए कास्टिंग चल रही है, जिनका मधुबाला की निजी जिंदगी में अहम रोल रहा।

इन एक्ट्रेसेस के नामों की थी चर्चा

मालूम हो कि मधुबाला के किरदार के लिए पहले कियारा आडवाणी से बातचीत चल रही थी, पर बात नहीं बन पाई और फिर सारा अर्जुन को साइन किया गया। इससे पहले मधुबाला के किरदार के लिए साई पल्लवी और अनीत पड्डा का नाम भी सामने आया, पर वो महज अफवाह निकली। मधुबाला की बायोपिक में उनके करियर और निजी जिंदगी के कई अहम पहलुओं को दिखाया जाएगा। उन पलों को भी दर्शकों को देखने का मौका मिला, जिनसे वो अछूते हैं। साथ ही दिलीप कुमार और किशोर कुमार के साथ मधुबाला के रिश्ते, स्ट्रगल और दर्द की कहानी भी दिखाई जाएगी।

मनीष मल्होत्रा भी बनाने वाले थे मधुबाला पर बायोपिक

मधुबाला पर बायोपिक बनाने के लिए फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का भी नाम सामने आया था, पर दिवंगत एक्ट्रेस की बहन मधुर भूषण ने 2022 में कह दिया था कि मधुबाला की जिंदगी पर फिल्म सिर्फ वो और उनकी टीम ही बनाएगी, बाकी कोई और नहीं बनाएगा।

समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है शासकीय योजनाओं का लाभ : विधायक मरपची

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

सुशासन तिहार के अंतर्गत मरवाही जनपद के अंतिम छोर के कलस्टर ग्राम पंचायत सेमरदर्री में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में 18 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने उपस्थित होकर विभिन्न मांगो, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए और विभागीय स्टॉलों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्राप्त किए। शिविर में विधायक प्रणव कुमार मरपची एवं कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन और जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी-कमर्चारी उपस्थित हुए। जनप्रतिनिधियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों के संबंध में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली।

विधायक प्रणव कुमार मरपची ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जनकल्याकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने

और आमजनों की समस्याओं का प्रभावी निराकरण के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के दौरान जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेमरदर्री मरवाही जनपद के अंतिम छोर का गांव है। यहां आयोजित शिविर में 18 ग्राम पंचायतों के लोगों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी पंचायत के ग्रामीण किसी भी शिविर में जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से शासन की योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है।

जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा एवं उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह तथा जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बूंदकुंवर मास्को ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजनों की सुविधा के लिए 1 मई से 10 जून तक जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने शिविरों में ग्रामीण जनों को उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराने तथा विभिन्न योजनाओं को सुनने, समझने और पात्रता के अनुसार उसका लाभ लेने कहा।

कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में सुशासन तिहार के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उददेश्य आमजनों की समस्याओं का समाधान करना और योजनाओं की जानकारी देना तथा पात्रता अनुसार लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि शिविर में सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। शिविर में मांग एवं शिकायत से संबंधित कुल 616 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर निराकृत होने वाले प्रकरणों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से निराकृत करने भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण, ड्राइविंग लाइसेंस तथा ई-केवाईसी किया गया। जिले में 13 जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 10 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 3 शिविर नगरीय निकायों में शामिल हैं।

शिविर में सभी विभागों के जिला अधिकारियों द्वारा बारी-बारी से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई तथा विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। राजस्व विभाग द्वारा 11 हितग्राहियो को आबादी पटटी, एक हितग्राही को वन अधिकार फौती पश्चात किसान किताब और एक हितग्राही को नवीन किसान किताब वितरित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को ड्राइविंग लाईसेंस, मछली पालन विभाग द्वारा दो हितग्राहियों को जाल एवं ट्रे और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत चार गर्भवती माताओं की गोदभराई, एक बच्चे का अन्न प्राशन और 11 बालिकायों को नोनी सुरक्षा योजना से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरदर्री के कक्षा 10वीं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त दो विद्यार्थीयों को सम्मानित भी किया गया।

शिविर में जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राधा मुरारी लाल रैदास, जनपद सदस्य श्रीमती किशमिश भानू, किशन ठाकुर, हेमचंद मरावी, अजय रजक, शंकर चक्रधारी, पारस चौधरी, महेश पाव, दिनेश मास्को, श्रीमती गंगोत्री मास्को, श्रीमती ममता पाव, एसडीएम देवेन्द्र सिरमोर, तहसीलदार प्रीती शर्मा, सीईओ विनय सागर सहित विभिन्न विभागों के जिला, अनुविभाग एवं खण्डस्तरीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

खास खबर

भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ ने किया श्रमिकों का सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा भाजपा कार्यालय दुर्ग में श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेजा, हमाल, कुली, मिस्त्री सहित विभिन्न निर्माण कार्यो से जुड़े मेहनतकश श्रमिकों का तिलक लगाकर, श्रीफल एवं गमछा भेंट कर सम्मान किया गया तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के सहसंयोजक एवं दुर्ग संभाग प्रभारी दिनेश देवांगन उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता जिला संयोजक दिनेश मिश्रा ने की तथा संचालन राकेश दुग्गड़ ने किया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि रोजी-मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले वृद्ध श्रमिक बैसाखू राम साहू को अतिथि मंच पर स्थान देकर सम्मानित किया गया। इस भावनात्मक क्षण ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता अजय तिवारी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अरविंदर खुराना, झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ सहसंयोजक दीपक सिन्हा, मंडल अध्यक्ष कमलेश फेकर, कमलेश साहू, सोशल मीडिया प्रभारी रजनीश श्रीवास्तव, नवीन साहू, उमेश गोस्वामी, अविनाश कुमार, कमलेश अवस्थी सहित बड़ी संख्या में श्रमवीर पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहीं।

सम्मान समारोह में बरसात, धूप और कठिन परिस्थितियों में निरंतर श्रम कर समाज और देश के निर्माण में योगदान देने वाले मजदूरों के परिश्रम को नमन किया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि श्रमिक वर्ग देश की प्रगति की मजबूत नींव है। मुख्य अतिथि सुरेंद्र कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि मजदूर देश और समाज की वास्तविक शक्ति हैं। उनके बिना विकास की कल्पना अधूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें श्रमिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार श्रमिकों के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे मजदूर परिवारों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। विशिष्ट अतिथि दिनेश देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निश्चित प्रीमियम राशि जमा करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती देने की दिशा में कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में जिला संयोजक दिनेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा गरीब मजदूर व दलीतो कि उत्थाथन में कार्य करने वाली पार्टी है उन्होंने श्रमिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि मजदूरों का सम्मान करना समाज का नैतिक दायित्व है, क्योंकि श्रमिकों के परिश्रम से ही विकास की मजबूत इमारत खड़ी होती है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने श्रमिकों को दी शुभकामनाएं

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी श्रमिक भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि श्रमिकों के परिश्रम और समर्पण से देश और प्रदेश के विकास की मजबूत नींव तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन में खुशहाली और सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार श्रमिकों और आम जनता के हित में योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।

शासन आपके द्वार, समाधान हर घर तक, जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए समाधान शिविरों का आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सुशासन तिहार 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में समाधान शिविरों के आयोजन के लिए तिथि और स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इन शिविरों में नागरिकों से उनकी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहकर यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक लोगों को शिविरों में लाभान्वित किया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।

सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य शासन-प्रशासन को सीधे आमजन तक पहुंचाना और उन्हें कार्यालयों के चक्कर से राहत देना है। इस पहल के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। अभियान से लंबित प्रकरणों का तेजी से निपटारा होगा, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और जनभागीदारी

को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

विकासखंड बेमेतरा : विकासखंड बेमेतरा में 6 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 5 मई को ग्राम पंचायत मोहरेगा, 8 मई को सेमरिया, 13 मई को धोलिया, 18 मई को खिलोरा, 22 मई को चोरभट्ठी तथा 3 जून को बैहरसरी में शिविर लगाए जाएंगे।

विकासखंड बेरला : बेरला विकासखंड में कुल 5 शिविर आयोजित होंगे। 5 मई को सलधा, 15 मई को रेवे, 22 मई को आनंदगांव, 29 मई को सांकरा तथा 9 जून को लाटा में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

विकासखंड नवागढ़ : नवागढ़ में कुल 6 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 7 मई को मोहतरा, 12 मई को नारायणपुर, 18 मई को कुरा, 21 मई को कटई, 26 मई को झांकी तथा 4 जून को खेड़ा में शिविर लगाए जाएंगे।

विकासखंड साजा : साजा विकासखंड में भी 6 शिविर आयोजित किए जाएंगे। 6 मई को दर्री, 13 मई को घीवरी, 15 मई को टेलका, 19 मई को बिरनपुर, 22 मई को तेंदूभाठा तथा 3 जून को गाड़ाडीह में शिविर आयोजित होंगे।

नगरीय निकायों में 15 समाधान शिविर

नगरीय क्षेत्रों में भी आमजन की सुविधा के लिए 15 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर पालिका परिषद बेमेतरा में 13 मई को गांधी भवन वार्ड 4, 20 मई को सिंघोरी स्थित कबीर कुटी सांस्कृतिक मंच तथा 28 मई को भद्रकाली मंदिर परिसर में शिविर लगाए जाएंगे। नगर पंचायत भीभोरी में 14 मई, दाढ़ी में 28 मई, देवकर में 29 मई, कुसमी में 14 मई, मारो में 28 मई को शिविर आयोजित होंगे। नगर पंचायत नवागढ़ में 22 मई को वार्ड 15 सतनाम भवन, 28 मई को वार्ड 10 कार्यालय भवन और 3 जून को वार्ड 14 टाउन हॉल में शिविर लगाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त परपोड़ी में 28 मई (वार्ड 7 मंगल भवन), साजा में 20 मई (वार्ड 13 नगर भवन), थानखमहारीया में 21 मई (नगर पंचायत कार्यालय) तथा बेरला में 5 जून को नगर पंचायत कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। सुशासन तिहार 2026 केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह पहल ह्रसरकार आपके द्वारह्र की अवधारणा को साकार करते हुए प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करेगी।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदर साहू पेट्रोलियम का किया शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

लखनपुर में बिलासपुर नेशनल हाईवे- 130, राजपुरीकला स्थित सदर साहू पेट्रोलियम का शुक्रवार को छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मंत्री अग्रवाल ने सबसे पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल पंप की सेवाओं का शुभारंभ किया।

मंत्री श्री अग्रवाल ने पेट्रोल पंप के संचालक सुरेश साहू को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 130 पर इस तरह की सुविधाओं के शुरू होने से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने क्षेत्र के विकास में निजी निवेश की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ऐसे प्रयासों को सराहनीय बताया। मंत्री श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पेट्रोल पंप जैसे प्रतिष्ठान न केवल सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति देते हैं। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कमल भान सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने इस नई सुविधा के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

डबल इंजन सरकार से छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा विकास- सांसद पाण्डेय

सुशासन तिहार 2026 : जिले में कवर्धा से जन समस्या निवारण शिविर का हुआ शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप प्रदेश में सुशासन तिहार के तहत जन शिकायतों के त्वरित निराकरण की दिशा में कवर्धा के वीर सावरकर भवन से जन समस्या निवारण शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सांसद संतोष पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा तथा नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे। अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर योजनाओं की जानकारी ली।

शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने हितग्राहियों से सीधा संवाद किया और उनके आवेदन प्राप्त कर कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। शिविर में ट्रायसाइकिल, राशनकार्ड सहित साक्षी राजपूत को सक्षम योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 80 हजार का चेक प्रदान किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर में 85 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल, वार्डो के पार्षदगण सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जन समस्या निवारण शिविर के दौरान सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि छत्तीसगढ़

में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्ति का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तभी संभव है, जब वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी मुख्यधारा से जुड़ें। इसी उद्देश्य से नक्सल मुक्ति और पुनर्वास अभियान चलाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है।

सांसद श्री पाण्डेय ने बताया कि अब इन वनांचल क्षेत्रों में पुल-पुलिया, सड़क, शिक्षा संस्थान, एजुकेशन हब, मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही तेंदूपत्ता की खरीदी 5500 रुपए प्रति मानक बोरी की दर से की जा रही है, जिससे वनवासियों और आदिवासियों को आर्थिक संबल मिल रहा है। सांसद ने कहा कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को बराबरी पर नहीं लाया जाएगा, तब तक सुशासन की कल्पना अधूरी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आवास, भोजन, कपड़ा, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं आमजन तक पहुंचाई जा रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य तेजी से जारी है।

सांसद श्री पाण्डेय ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर-घर गैस कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत डायलिसिस, स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सांसद श्री पाण्डेय ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने नजदीकी शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं रखें तथा आवेदन दें। उन्होंने कहा कि शिविरों में स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर विभिन्न विभागीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। सभी को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, ताकि समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन सीधे जनता तक पहुंच रहा है। यह अभियान शासन और आम नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि शिविरों के जरिए जनता के छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। शासन ने जनसेवा का जो संकल्प लिया है, उसे पूरी प्रतिबद्धता और कृतज्ञता के साथ निभाया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि गांव, शहर और वार्ड स्तर तक शासन की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। शिविरों में आवेदन लेने से लेकर उनके निराकरण तक की पूरी प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है। आधार कार्ड अपडेट, राशन कार्ड, विभिन्न प्रमाणपत्रों को बनाना जैसे कार्य तत्काल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों का निराकरण मौके पर संभव नहीं है, उन्हें संबंधित उच्च कार्यालयों को भेजा जा रहा है, जहां उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चंद्रवंशी ने कहा कि आम जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान करना ही शासन का लक्ष्य है। सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर उनका शीघ्र और प्रभावी निराकरण किया जा रहा है।

जिले के इन स्थानों में किया जाएगा शिविर का आयोजन

सुशासन तिहार के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार आगामी 04 मई को झलमला (बोड़ला), 05 मई को चारभांठा, 06 मई को अमनिया, 07 मई को बम्हनी, चिल्फी, 08 मई सामुदायिक भवन पंडरिया, 11 मई को उसरवाही, 12 मई को बिरनपुर, 13 मई को रणवीरपुर, 14 मई को घुटुरकुण्डी, 15 मई को तरेगांव जंगल, 18 मई को मक्के, 19 मई को सहसपुर लोहारा, 20 मई को खैरझिटी पुराना, 21 मई को इंदौरी, 22 मई को खडौदाकला, 25 मई को गांगपुर, 26 मई को सेन्हाभठा, पंडरिया, 28 मई को जेवडनखुर्द, 29 मई को मिनमिनिया मैदान, सर्व मांगलिक भवन वार्ड 07 बोड़ला, 01 जून को सिंघनपुरी जंगल, 02 जून को अंधियारखोर, 03 जून को खैरबनाकला, 04 जून को नगर पंचायत पाण्डातराई, 05 जून को सर्व मांगलिक भवन बोड़ला, 08 जून को दामापुर, 09 जून को गेगड़ा और 10 जून को सर्व मांगलिक भवन वार्ड 15 पिपरिया में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संवाद प्रमुख व मानपुर मोहला प्रभारी शारदा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया श्रमिक दिवस

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संवाद प्रमुख एवं मानपुर मोहला प्रभारी शारदा गुप्ता ने मोहला मानपुर कार्यकर्ताओं के साथ जिला मोहला मानपुर चौकी में भाजपा जिला स्तरीय मजदूर दिवस मनाया गया। जिसमे शारदा प्रसाद गुप्ता प्रदेश संवाद प्रमुख एवं जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रभारी मोहला मानपुर एवं अनिल सिंग राष्ट्रीय कायर्कारिणी सदस्य भारतीय इस्पात मजदुर महासंघ प्रभारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ मोहला मानपुर के प्रभारी शारदा गुप्ता एवं भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला के अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने भारत माता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की। अपने संबोधन में प्रदेश संवाद प्रमुख शारदा गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हैं वह हमारे श्रमिक भाइयों तक जन-जन तक पहुंचे। इसकी

चिंता हम सबको करनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकर ने देश में अभूतपूर्व क्रांति पैदा की है जो कार्य देश के आजादी के बाद वर्षो तक नहीं हुए वे आज इन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं स्वास्थ्य सुविधा की आप देखें तो देश में लगभग 6 एम्स थे वह अभी 26 एम्स बन गए 320 मेडिकल कॉलेज थे अब 735 मेडिकल कॉलेज बने कोविड काल में सरकार ने लोगों को न केवल टीका उपलब्ध कराकर उनकी जान को सुरक्षित किया बल्कि विदेशों मे भी हमने लोगों की जान बचाई है।

पहले श्रमिक भाई इलाज के लिए अपने खेतों को बेच दिया करते थे अपने घर को बेच दिया करते थे सरकार ने उनका मुफ्त इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कराई गई एम्स हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाई गई अपितु लगभग 50 करोड लोगों को आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया। हम सभी साथियों को जन-जन तक सरकार की इन नीतियों को उनके घर तक पहुंचना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास मे लगभग देश में 9 करोड लोगों को आवास उपलब्ध कराया है।

उज्जवला गैस योजना के अंतर्गत हमारे निर्धन वर्ग को निशुल्क गैस उपलब्ध कराया सुलभ शौचालय बनाकर देश में एक स्वच्छता की नई क्रांति पैदा की गई। हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करके देश में युवाओं के लिए रोजगार और देश को उन्नत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज देश में आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद सभी समाप्ति की ओर है लोग भारतीय जनता पार्टी के कायर्कार को देखकर उनसे जुड़ रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है मुख्यमंत्री से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी जेल जा चूके हैं लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति भय व्याप्त है। हमारे श्रमिक भाइयों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपए से लेकर 21रुपये मे बीमा की योजना लागू की जिससे हमारे श्रमिक भाइयों को लाभ मिल रहा है श्रमिक कानून में आज भी सुधार की आवश्यकता है शोषण से मुक्ति की आवश्यकता है।

जिस पर सरकार लगातार कार्य कर रही है मजदूरों के काम करने की समय निश्चित हो उन्हें उचित वेतनमान मिले यह हम सब का भी दायित्व है कि इस पर निगरानी रखी जाए भारतीय जनता पार्टी जिला मोहल्ला के अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी ने भी अपने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं से मजदूरों के शोषण और उनकी आवाज बुलंद करने पर बल दिया। भारतीय इस्पात मजदूर संघ के राष्ट्रीय कायर्कारिणी सदस्य वह भिलाई इस्पात संयंत्र के सीपीएफ ट्रस्टी अनिल सिंह ने भी मजदूरों के हितों के लिए और भी कार्य किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह, जिला उपाध्यक्ष रमेश हिडाम, जिला महामंत्री नरसिंह भंडारी, जिला कोषाध्यक्ष राजेश जैन सहकारिता प्रकोष्ठ, अंबर जोशी, जिला महिला मोर्चा महामंत्री सुरेखा मंडावी, ग्राम पंचायत सरपंच गजेन्द्र पुराम , जिला पंचायत सदस्य लखन कलामे, मोहला मंडल महा मंत्री मनोज नेताम, सनानंद तारम, कौडीकसा मंडल अध्यक्ष संदीप साहू महामंत्री झनक सोनवानी, जिला झुग्गी झोपडी संयोजक कृष्णा यादव सह संयोजक विक्रांत निकोशे / दिलीप कौशिक/ नरेश मेश्राम जी भाजपा कार्यकता तथा ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर कामगारों को गमझा और श्री फल देकर उनका सम्मान किया गया ।जिसमे गीतम यादव , लक्की यादव , धंजु नांगवंशी, तरूण नेताम , खेमचंद कुंजाम , रोहित कोठारी ,श्यामशाय यादव,रवि साहू , आलोक सैकड़ो लोग उपस्थित थे।

दिनेश अवस्थी हुए सेवानिवृत्त, दी गई विदाई

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक राजनांदगांव में सहायक प्रबंधक (फील्ड ऑफिसर) के पद में कार्यरत दिनेश अवस्थी पिता श्री स्व. दुलारे अवस्थी सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्हें बैंक कर्मियों ने ससम्मान भावभीनी विदाई दी। दिनेश अवस्थ बैंक कर्मियों, किसानों और खाताधारकों के बीच अपने मिलनसार व्यवहार की वजह से लोकप्रिय हैं।

पुलिस परिवार के 23 बच्चों को मिला उड़ान का सपना

नई दृष्टिबिंदु / मुंगेली

पुलिस परिवार कल्याण योजना के तहत मुंगेली पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए पुलिस कर्मियों के 23 बच्चों को पायलट बनने के लिए प्रेरित करने हेतु स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, रायपुर का शैक्षणिक भ्रमण कराया। यह कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के संरक्षण, आईजी बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन और एसएसपी मुंगेली भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में इउअर रायपुर के सहयोग से आयोजित हुआ।

सीधा संवाद बच्चों ने फाइटर पायलट विंग कमांडर विवेक कुमार साहू और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों से बातचीत की। पायलट और तकनीशियन बनने की प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक व चिकित्सा मानकों की जानकारी दी गई। छात्रों ने प्रशिक्षण विमान का अवलोकन किया और कॉकपिट के उपकरणों व नियंत्रण प्रणाली को करीब से समझा। करियर मार्गदर्शन भारतीय वायु

सेना, थल सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, नागरिक उड्डयन और उक्त्रक्षे्में उपलब्ध करियर विकल्पों पर विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को हवाई अड्डे की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और विमान संचालन की बारीकियों से भी अवगत कराया गया।

हमारा उद्देश्य पुलिस परिवार के बच्चों का सर्वांगीण विकास और उज्ज्वल भविष्य निर्माण है। इस भ्रमण से बच्चों में देश सेवा हेतु उड्डयन क्षेत्र में करियर बनाने की नई ऊर्जा जगी है। ऐसे कार्यक्रम

आगे भी जारी रहेंगे। बच्चों के लिए यह भ्रमण बेहद प्रेरणादायक रहा। एक छात्र ने कहा, कॉकपिट में बैठकर लगा जैसे सपना सच हो गया। अब मैं भी पायलट बनकर देश की सेवा करूंगा। मुंगेली पुलिस की यह पहल बच्चों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई।

एसएसपी भोजराम पटेल

सत्ता के दबाव में पुलिस की अंधेरगर्दी, भाजपा नेता की झूठी शिकायत पर ग्रामीण को घंटों किया प्रताड़ित

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में सुशासन के दावों के बीच गुंडागर्दी और पुलिस प्रशासन की मनमानी का मामला सामने आया है। ताजा मामला ग्राम पारीकला का है, जहाँ एक भाजपा नेता की कथित झूठी शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एक ग्रामीण को घंटों हिरासत में रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस घटना के विरोध में कांग्रेस ने देर रात थाने का घेराव कर तीखा आक्रोश व्यक्त किया।

क्या है पूरा मामला?

शुक्रवार को ग्राम पारीकला निवासी दीपक दास मानिकपुरी के खिलाफ एक भाजपा नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव में सिटी कोतवाली पुलिस ने बिना किसी निष्पक्ष जांच के तत्काल ग्रामीण को गांव से उठा लिया। पुलिस ने उसे करीब पांच घंटे तक थाने में बिठाए रखा और मामूली बात पर जेल भेज देने की धमकी दी। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने दूसरे पक्ष (शिकायतकर्ता) को थाने बुलाने या उनसे पूछताछ करने की जहमत तक नहीं उठाई।

कांग्रेस ने घेरा थाना, पुलिस को दी चेतावनी

ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को वास्तविकता बताने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। घटना की सूचना मिलते ही शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रात 9 बजे सिटी कोतवाली का घेराव कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे ह्यसत्ता की गुलामीह्न करार दिया। भारी विरोध और तीखी बहस के बाद अंततः पुलिस ने ग्रामीण को रिहा किया।

भाजपा का सुशासन सिर्फ ढकोसला : चेतन भानुशाली

उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चेतन भानुशाली ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राजनांदगांव में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी चरम पर है। उन्होंने कहा कि "एक तरफ भाजपा 'सुशासन तिहार' का ढोंग कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके नेता आम नागरिकों के अधिकार छीनने और उन्हें पुलिस के दम पर कुचलने में तुले हैं। निदोष और भोली-भाली जनता पर पुलिसिया अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का दुरुपयोग कर डराने-धमकाने की राजनीति का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे।" इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में राजनीतिक द्वेष के चलते किसी निदोष को प्रताड़ित किया गया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

अहिवारा को स्वच्छता में देश में नंबर-1 बनाने का लक्ष्य, जनप्रतिनिधियों ने संभाली कमान

नई दृष्टिबिंदु / नंदिनी अहिवारा

नगर पालिका अहिवारा में स्वच्छता अभियान को लेकर व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) प्रवीण सिंह गहलोत ने क्षेत्र का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा के नेतृत्व में उपाध्यक्ष अशोक बाफना सहित पार्षद पुरुषोत्तम वर्मा, इंद्रजीत राउत, ईश्वर शर्मा, प्रदीप कोचर, कृति शिवाले, इंद्राणी बंजारे, पुष्पा साहू, केशव महिलांग एवं मीना जोशी उपस्थित रहे। इस दौरान महिला सफाई कर्मचारी, महिला रिक्शा चालक, नगर पालिका स्टाफ और स्थानीय नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली। जनप्रतिनिधियों ने स्वयं सड़कों पर उतरकर सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

सीएमओ प्रवीण गहलोत ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नगर को साफ-सुथरा बनाए रखने में सभी की भागीदारी जरूरी है। अहिवारा सीएमओ प्रवीण गहलोत जानकारी दी कि पूर्व में बिल्हा में पदस्थ रहने के दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण में बिल्हा ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार अहिवारा को भी स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में प्रथम स्थान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम के अंत में नागरिकों से अपील की गई कि वे कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें और नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में सहयोग करें।

दुर्ग में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, चलती कार में चल रहा था खेल; चार गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

थाना छावनी पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चलती कार में बैठकर फ्ळइ और गुजरात टाइटन्स के मैच पर सट्टा खिला रहे थे। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और लाखों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं।

30 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली कि हुंडई वेन्यु कार में कुछ युवक नेहरू नगर, सुपेला चौक और पावर हाउस इलाके में घूम-घूमकर मोबाइल से ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। पुलिस ने तत्काल वैकुण्ठ धाम गेट, गौरव पथ रोड, कैम्प-2 भिलाई के पास घेराबंदी कर कार समेत पवन कुमार यादव और मयंक गणवीर को दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने नमन गुप्ता और नीलकंठ कोसरे उर्फ नीलू के नाम उजागर किए। पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आईडी से सट्टा संचालित करते थे। व्हाट्सएप पर हिसाब-किताब रखते और कमाई को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे। जांच में खुलासा हुआ कि जब्त पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड दूसरों के नाम पर हैं, जिनका इस्तेमाल बिना जानकारी के लेनदेन में किया जा रहा था।

गिरफ्तार आरोपी में पवन कुमार यादव, 23 वर्ष, न्यू संतोषी पारा, कैम्प-2 भिलाई, मयंक गणवीर, 23 वर्ष, प्रगति नगर, रिसाली , नमन गुप्ता, 26 वर्ष, स्मृति नगर, सुपेला भिलाई, नीलकंठ कोसरे उर्फ नीलू, 21 वर्ष, ग्राम बरहापुर, धमधा, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कई सिम कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और सट्टे से जुड़े डिजिटल सबूत।

पुलिस ने आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 और इठर की धारा 111, 317(2), 317(4), 318(4), 61(2)(ए) के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन सट्टा या किसी अवैध आर्थिक गतिविधि में शामिल न हों। ऐसी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सट्टा संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फोरलेन सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग मिनी माता चौक पुलगांव से जेल तिराहा चौक तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। साथ ही पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य को भी समानांतर रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती और लगातार निरीक्षण का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। पोटिया चौक सहित कई स्थानों पर अतिक्रमणकर्ताओं ने कार्रवाई से पहले ही स्वयं अपने कब्जे हटाने शुरू कर दिए हैं, जिससे सड़क चौड़ीकरण का कार्य आसान हो गया है। जानकारी के अनुसार करीब 120 से अधिक लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण किए गए थे। इनमें दुकानें, बाउंड्रीवाल, शेड और अन्य निर्माण शामिल हैं, जो प्रस्तावित कार्य में बाधा बन रहे थे। निगम और ढहऊकी संयुक्त टीम इन अवरोधों को हटाने में लगातार जुटी हुई है। अतिक्रमण दल के प्रभारी सहायक अभियंता गिरीश दीवान ने बताया कि 30 अप्रैल से लगातार निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है।

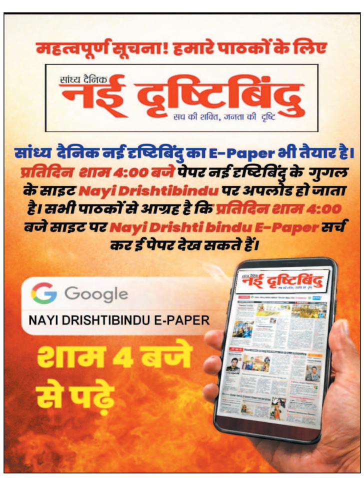

जामुल में घर से चल रहा था गांजे का धंधा, पुलिस ने महिला को दबोचा, 2.88 किलो गांजा जब्त

भिलाई। दुर्ग पुलिस के नशे के खिलाफ अभियान में जामुल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में चल रहे गांजा बिक्री के अड्डे का भंडाफोड़ कर पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 किलो 880 ग्राम गांजा और नगदी बरामद हुई। मामले में एक नाबालिग की संलिप्तता भी सामने आई है। 1 मई की सुबह करीब 9 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि पीएम आवास, 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई में एक महिला घर में गांजा रखकर बेच रही है। जामुल पुलिस ने बिना देर किए बताए गए मकान पर दबिश दी।

तलाशी में एस. निमर्ला, उम्र 32 वर्ष, के घर से सफेद बोरी में रखा 2 किलो 880 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 44 हजार रुपये है। मौके से 500 रुपये नगद भी जब्त किए गए। जांच में एक विधि से संघर्षरत बालक की संलिप्तता भी मिली है। पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत उसकी अलग से कार्रवाई की है। महिला आरोपी एस. निमर्ला, निवासी मकान नंबर 20/8 पीएम आवास, के खिलाफ थाना जामुल में अपराध क्रमांक 290/2026 धारा 20(ख), 27(क) NDPS Act के तहत केस दर्ज कर 2 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। दुर्ग पुलिस लगातार सूखा नशा और गांजे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग कर समाज को नशामुक्त बनाने में मदद करें।

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100